सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 178, नई दिल्ली । शनिवार, 07 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 अमानतुल्लाह गिरफ्तारी : "आप" का जबरदस्त प्रदर्शन
06 जेनरेटिव एआई और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियां भविष्य...
08 त्रिशूला सुभाष चंद्र बोस ब्रिज पर भीषण दुर्घटना, 2 लोगों की गई जान

वास्तविक समय की बुनियादी बातों पर डीडीई प्लेटफॉर्म को वाहन पोर्टल से जोड़कर हाइपोथेकेशन समाप्ति प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड) का प्रस्ताव

संजय बाटला

नंबर RT-11036/05/2024-MVL

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमवीएल अनुभाग) भारत सरकार

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

कार्यालय स्मरण

विषय: डीडीई प्लेटफॉर्म को वाहन पोर्टल से जोड़कर हाइपोथेकेशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एनईएसएल (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड) के प्रस्ताव के संबंध में बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी को 22 अगस्त, 2024 को दोपहर 12:00 बजे अतिरिक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संदर्भ लेने तथा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बैठक के कार्यवृत्त (अनुलग्नक-ए) को संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(एस.के. गीवा)

अवर सचिव, भारत सरकार फोन नं. 011-23739074 ई-मेल: geeva.sk@nic.in

संलग्न: उपरोक्तानुसार.

1. निदेशक (बीमा), वित्तीय सेवा विभाग को,
2. निदेशक (बैंक), वित्तीय सेवा विभाग
3. श्री. जॉयदीप शोम, डीडीजी और एचओजी एनआईसी
4. मिस नलिनी, एचओडी वाहन, एनआईसी
5. श्री. अवनीश, एचओडी इंफ्रा, एनआईसी
6. श्री. करुणेश कुमार, एनआइसी
7. केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और गुजरात राज्यों के परिवहन विभाग/प्रतिनिधि
8. एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक प्रतिनिधि
9. एआईएमटीसी, एआईटीडब्लूए, बीओसीआई प्रतिनिधि

कॉपी:

1. पीपीएस से एएस (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
2. निदेशक (एमवीएल) के प्रधान निजी सचिव
3. पीए टू यूएस (एमवीएल), एमओआरटी&एच

अनुबंध,

1. ऑटो हाइपोथीकेशन एंडोर्समेंट/समाप्ति के प्रस्ताव पर 22 अगस्त, 2024 को एनईएसएल के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त:

2. आरंभ में, अतिरिक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात, एनईएसएल ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा सभी हितधारकों को इसके लाभों के बारे में बताया और प्रतिभागियों से प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणियों/प्रश्नों के लिए अनुरोध किया।

3. निदेशक (बीमा), डीएफएस ने प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित चिंताएं उठाईं -

क्या कार्यक्षमता वाहन पोर्टल पर हाइपोथेकेशन एंडोर्समेंट/हाइपोथेकेशन समाप्ति की सत्यता/प्रामाणिकता की पुष्टि करती है।

बदलाव का समय क्या होगा और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय क्या होगा।

वित्तीय निहितार्थ लागत के आधार के संबंध में स्पष्टीकरण, और इसमें शामिल लागत बीमा कंपनियों को कौन वहन करेगा, क्या यह ग्राहकों/बैंकों पर होगा/

(कार्रवाई: एनईएसएल/एनआईसी)

4. एनईएसएल ने पुष्टि की है कि ग्राहकों और बैंकों के लिए कोई लागत शामिल नहीं है: हालांकि, बीमा कंपनियों के लिए निहितार्थ के बारे में विचार-विमर्श के बाद सूचित किया जाएगा। एमओआरटीएच ने निदेशक (बीमा) से अनुरोध किया है कि वह बैंकिंग क्षेत्र की देखभाल करने वाले डीएफएस में अपने समकक्ष के साथ प्रस्ताव साझा करें और इस पर टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्रदान करें।

(कार्रवाई: डीएफएस/एनईएसएल)

5. एआईएमटीसी, बीओसीआई और एआईटीडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का स्वागत किया है और सुझाव दिया है कि इस सेवा की पूरी प्रक्रिया संपर्क रहित/फेसलेस, तकनीक-संचालित, समयबद्ध और बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के होनी चाहिए।

(कार्रवाई: एनईएसएल/एनआईसी)

6 . एचडीएफसी/आईसीआईसीआई/एसबीआई बैंकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे पहले ही कुछ राज्यों के साथ एकीकृत हो चुके हैं और उनकी प्रक्रिया का प्रवाह थोड़ा अलग है। बैंकों के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और एनईएसएल का प्रस्ताव चालू होने के बाद वे इसमें शामिल होंगे। एनईएसएल को विभिन्न बैंकों के मौजूदा प्रक्रिया प्रवाह की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो निर्बाध समाधान के लिए संशोधित करने के लिए कहा गया था।

(कार्रवाई: एनईएसएल/बैंक)

7 . एनआईसी/एआईटीडब्ल्यूए/बीओसीआई/एआईएमटीसी ने एनईएसएल को नीचे उल्लिखित मुद्दों पर जांच करने और इनपुट साझा करने का सुझाव दिया है:-

"मोटर वाहनों के पुनर्वित्त मामले"
"विफलता प्रबंधन प्रणाली"
"ऋण चूककर्ताओं की पहचान की प्रक्रिया".

(कार्रवाई: एनईएसएल और एमओआरटी&एच)

8. सभी उपस्थित लोगों से एनईएसएल प्रस्ताव पर अपनी लिखित प्रतिक्रिया साझा करने का अनुरोध किया गया था।

(कार्रवाई: सभी)

9. बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया ट्रांसपोर्ट दिवस : आर के शर्मा

"ट्रांसपोर्ट उद्योग को बचाने के लिए आयोग बहुत जरूरी"

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर के शर्मा ने बिजवासन स्थित एसोसियेशन कार्यालय पर कार्यकारिणी के साथ ट्रांसपोर्ट दिवस मनाते हुए पूरे देश को ट्रांसपोर्ट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज देशभर में 100 से अधिक स्थानीय संगठनो के साथ 80 से ज्यादा एबीटीए के कार्यालयों पर तथा हजारों छोटे बड़े ट्रांसपोर्ट वालों ने बड़ी धूमधाम से ट्रांसपोर्ट दिवस मनाया। आर के शर्मा ने बताया अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देश के सभी संगठनो के साथ मिलकर हर वर्ष 6 सितंबर को ट्रांसपोर्ट दिवस मनाती है एसोसियेशन अच्छे कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित और सम्मानित करती है, पर्यावरण बचाने के लिए पूरे देश में ट्रांसपोर्ट एरिया में पेड़ लगाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाने के लिए मेडिकल, आई, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ड्राइवरों भाईयों को अच्छे संस्कार देने के लिए कैंप लगाते हैं, गर्त में जा रहे ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए ट्रांसपोर्टरों में भाईचारा और एकता बनाने और अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए देश भर में जगह-जगह संगोष्टियां करते हैं ट्रांसपोर्ट भाई अपने-अपने तरीके से भंडारे लगाकर, रागिनी, खेल प्रतियोगिता कराकर ट्रांसपोर्ट दिवस सेलिब्रेशन करते हैं उन्होंने बताया हमने दिल्ली में प्रधानमंत्री को पूरे देश की तरफ से ज्ञापन सौंप कर ट्रांसपोर्टोंरों के सम्मान के लिए 6 सितंबर ट्रांसपोर्ट दिवस तथा ट्रांसपोर्ट उद्योग को बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन शीघ्र अति शीघ्र करने के लिए ज्ञापन सोपा है हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार 20 करोड लोगों का पालन पोषण और देश की उन्नति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उद्योग को बचाने के लिए हमारी मांगों पर तुरंत प्रभाव से गौर करेगी और मुख्य दोनों मांगे पूरी करेगी इस अवसर पर अशोक कुमार, संजय शर्मा, एस के भारद्वाज, नरेंद्र शर्मा, सुनील मंडोली, कमल शर्मा, अरविंद गुप्ता, संदीप जांगड़ा, के पी शर्मा, राजेंद्र नंबरदार, पवन शर्मा, आलोक दुबे, सुनील लोहानी, अनंत शर्मा, जोगेंद्र, दिनेश कौशिक, शिवम आदि उपस्थित थे।

दिल्ली के महिपालपुर इलाके में धू-धूकर जल गई डीटीसी बस, बाल-बाल बचे यात्री

दिल्ली के महिपालपुर इलाके में डीटीसी बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई. जिस बस में आग लगी उसमें सवारियां भरी हुई थी. आग लगने की जानकारी मिलते ही सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

संजय बाटला

नई दिल्ली: दिल्ली में डीटीसी बसों में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. शुक्रवार शाम को भी महिपालपुर इलाके में डीटीसी बस में आग लगने की घटना सामने आई. जिस बस में आग लगी उसमें सवारियां भरी हुई थी. जानकारी के अनुसार, बस के इंजन में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और बस के अंदर से धुआं निकलने लगा. इतने में बस में बैठे सभी सवारी, बस ड्राइवर और कंडक्टर बस से बाहर निकल गए. शुरुआत में खुद आग को बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चंद मिनट में ही बस आग के गुब्बार में तब्दील हो गया.

दरअसल, यह घटना महिपालपुर इलाके की है. महिपालपुर काफी व्यस्त मार्केट है. एयरपोर्ट पास होने के कारण यह मार्केट हमेशा बिजी रहता है. बस में जिस प्रकार से आग लगी, उसकी लपटों से आसपास के बिल्डिंग के बाहरी हिस्से को भी नुकसान हुआ है. साथ ही रोड पर खड़े एक स्कूटी और एक बाइक भी आग की चपेट में आ गए. यह रास्ता आईजीआई एयरपोर्ट से दक्षिण दिल्ली जाने के लिए मुख्य मार्ग है. बस में आग लगने के कारण इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर ट्रैफिक पुलिस द्वारा डायवर्ट कर दिया गया है.

आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद डीटीसी बस में लगी आग पर काबू पाया गया. इस आगजनी की घटना ने महिपालपुर के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया था, लिहाजा इस बस को आग बुझाने के बाद यहां से हटाने में काफी वक्त लग गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आग के चलते किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन बस की आग के लपटों की वजह से बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है।

नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहन निर्माताओं से ग्राहकों को रियायती हेलमेट उपलब्ध कराने का किया आग्रह

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहन निर्माताओं को वाहन खरीदने वालों को छूट या उचित दर पर हेलमेट उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान चली जाती है। गडकरी ने बुधवार को दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ₹मैं दोपहिया वाहन निर्माताओं से अनुरोध करने के बारे में सोच रहा हूं... अगर वे वाहन खरीदने वालों को हेलमेट पर कुछ उचित छूट दे सकें, तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं।" सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने स्कूल बसों के लिए पार्किंग व्यवस्था की योजना बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गडकरी ने कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा देश के हर तालुका में ड्राइविंग स्कूल शुरू करने की है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यातायात उल्लंघनों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस पर गौर करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन वास्तव में प्रभावी प्रवर्तन भी एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संकलित "अनजाने में चोट लगने की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रणनीति" नामक एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें अनजाने में लगी चोटों के कारण होती हैं। जो कि ऐसी मौतों का 43 प्रतिशत से अधिक है। जिसमें तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना सबसे बड़ा कारण है।

इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव भारतीय तेल और गैस उद्योग पर

संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का आगमन वैश्विक परिवहन और ऊर्जा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कई देशों में पर्यावरणीय समस्याओं, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के कारण ईवी का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। भारतीय परिवहन उद्योग में ईवी के बढ़ते उपयोग का प्रभाव न केवल वाहनों की बिक्री और निर्माण पर होगा, बल्कि इसका व्यापक असर तेल और गैस उद्योग पर भी पड़ेगा, जो दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ रहा है।

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। यहां तेल की भारी मांग मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है, जहां पेट्रोल और डीजल वाहनों का वर्चस्व है। भारतीय वाहन उद्योग में बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या अधिक है, जिसके कारण देश की कुल तेल खपत का एक बड़ा हिस्सा परिवहन में जाता है। भारतीय तेल और गैस उद्योग कई दशक से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के आगमन के साथ यह उद्योग कई नए चुनौतियों का सामना कर रहा है।

पहली और सबसे स्पष्ट चुनौती तेल की मांग में संभावित कमी है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी, ईंधन के पारंपरिक स्रोतों जैसे पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आना तय है। ईवी सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करते हैं, जिससे तेल रिफाइनरियों और वितरण नेटवर्क के लिए यह एक प्रमुख चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया धीरे-धीरे हो रही है और ईवी के बढ़ते उपयोग के बावजूद पेट्रोल और डीजल की पूरी तरह से जगह लेना अभी दूर की बात है, फिर भी दीर्घकालिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

दूसरी चुनौती तेल और गैस उद्योग के लिए आर्थिक पहलू है। तेल और गैस से संबंधित उत्पादों पर भारी कर लगने के कारण यह उद्योग भारत सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्य सरकारें भारी कर लगाती हैं, जो कुल सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनता है। अगर ईवी का उपयोग बढ़ता है और पारंपरिक ईंधन की मांग कम होती है, तो सरकार के लिए यह राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसलिए, तेल और गैस उद्योग पर ईवी के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय सरकार को भी अपने राजस्व मॉडल पर विचार करना होगा।

तीसरा प्रभाव यह है कि ईवी का विस्तार तेल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर डालेगा। भारत में तेल उद्योग में एक बड़ी आपूर्ति श्रृंखला शामिल है, जिसमें रिफाइनरियों, वितरण नेटवर्क, पाइपलाइनों और पेट्रोल पंपों का व्यापक नेटवर्क शामिल है। यदि पेट्रोल और डीजल की मांग में कमी आती है, तो इस नेटवर्क की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे संबंधित उद्योगों में नौकरियों की संभावित कमी हो सकती है। पेट्रोल पंपों और वितरण केंद्रों में भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यदि भविष्य में ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती है, तो पारंपरिक ईंधन स्टेशन धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में परिवर्तित हो सकते हैं।

तेल और गैस उद्योग को पर्यावरणीय और स्थिरता की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत, जैसा कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी करना चाहता है, वह भी ईवी को बढ़ावा दे रहा है। ईवी को अपनाने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जो देश के प्रमुख शहरों में एक बड़ी समस्या है। पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहन प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत हैं, और उनके स्थान पर ईवी का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है।

इससे न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य के संदर्भ में भी लाभ होगा, क्योंकि भारत के कई शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आते हैं।

इस बीच, तेल और गैस उद्योग को अपने व्यवसाय को फिर से आकार देने की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा, तेल और गैस उद्योग को अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे कि प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल की ओर बढ़ना होगा। कुछ तेल कंपनियां पहले से ही अपनी रणनीतियों को बदल रही हैं और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। जैसे-जैसे दुनिया ऊर्जा संक्रमण की दिशा में आगे बढ़ रही है, तेल कंपनियों को अपनी भविष्य की योजनाओं को फिर से देखना होगा ताकि वे अपने व्यापार को सुरक्षित रख सकें।

यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि ईवी का आगमन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक चुनौती है। यदि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ता है, तो तेल आयात पर निर्भरता में कमी आ सकती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। इसके साथ ही, यह भारत के चालू खाता घाटे को भी कम कर सकता है, क्योंकि तेल आयात पर खर्च कम हो सकता है।

हालांकि, इस बदलाव के लिए एक समग्र नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। सरकार को एक स्थिर और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना होगा, ताकि ईवी का उपयोग आसान हो सके। इसके अलावा, बैटरी निर्माण और रिसाइक्लिंग के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता होगी। यदि भारत में बैटरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे न केवल परिवहन क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि यह भारत के उद्योग के लिए एक नया अवसर भी प्रदान करेगा।

अंत में, भारतीय तेल और गैस उद्योग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। जहां एक ओर तेल की मांग में संभावित कमी और राजस्व नुकसान की चिंता है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर भी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, जहां उन्हें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटकर हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता होगी। तेल और गैस उद्योग को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना होगा और अपने व्यापार मॉडल में बदलाव करना होगा ताकि वे भविष्य में भी प्रासंगिक बने रह सकें।

इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव भारतीय तेल और गैस उद्योग पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होगा, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उद्योग, सरकार और समाज किस प्रकार इस बदलाव को अपनाते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं।

राष्ट्रीय एकता का पर्व है गणेशोत्सव

गणपति बप्पा मोरिया

भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी नए काम को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने के बाद प्रारंभ होने वाला कार्य हर हाल में पूरा होगा।

गणेश शब्द का अर्थ होता है जो समस्त जीव के ईश अर्थात स्वामी हो। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक। वैदिक मत में सभी कार्य के आरम्भ जिस देवता का पूजन से होता है वही विनायक है। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्त्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्नो के नाश करने और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में काफी जोश के साथ मनाया जाता है। किन्तु महाराष्ट्र में विशेष रूप से गणेशोत्सव को 10 दिनों तक बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को गणेशोत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है।

पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेशजी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी-बड़ी प्रतिमायें स्थापित की जाती है। इन प्रतिमाओं का नो दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करने पहुंचते है। नो दिन बाद गणेश प्रतिमाओं को समुद्र, नदी, तालाब में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी मनाने के दौरान लोग भगवान गणेश की पूजा करते है। गणेश हिन्दू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता है। यह उत्सव खासतौर से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हालाँकि अब ये भारत के लगभग सभी राज्यों में मनाया जाने लगा है। गणेश चतुर्थी पर लोग पूरी भक्ति और श्रद्धा से ज्ञान और समृद्धि के भगवान की पूजा करते है।

भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी नए काम को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने के बाद प्रारंभ होने वाला कार्य हर हाल में पूरा होगा। भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने से दो-तीन महीने पहले ही कारीगर भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। गणेशोत्सव के दौरान बाजारों में भगवान गणेश की अलग-अलग मुद्रा में बेहद ही सुंदर मूर्तियां मिल जाती है। गणेश चतुर्थी वाले दिन लोग इन मूर्तियों को अपने घर लाते हैं। कई जगहों पर 10 दिनों तक पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं जहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती हैं। प्रत्येक पंडाल में एक पुजारी होता है जो इस दौरान चार विधियों के साथ पूजा करते हैं। सबसे पहले मूर्ति स्थापना करने से पहले प्राणप्रतिष्ठा की जाती है। उन्हें कई तरह की मिठाईयां प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं। गणेश जी को मोदक काफी पंसद थे। जिन्हें चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनाया जाता है। इस पूजा में गणपति को लड्डूओं का भोग लगाया जाता है।

इस त्योहार के साथ कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं जिनमें से उनके माता-पिता माता पार्वती और भगवान शिव के साथ जुड़ी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। शिवपुराण में रुद्रसंहिता के चतुर्थ खण्ड में वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया था। भगवान शिव ने जब भवन में प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे पार्वती नाराज हो उठीं। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिवजी के निर्देश पर विष्णुजी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव (हाथी) का सिर काटकर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया।

महान क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 मे वन्देमातरम नामक एक गीत लिखा था। जिस पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा कर गीत गाने वालों को जेल मे डालने का फरमान जारी कर दिया था। इन दोनों बातों से लोगो मे अंग्रेजो के प्रति बहुत नाराजगी व्याप्त हो गयी थी। लोगो मे अंग्रेजो के प्रति भय को खत्म करने और इस कानून का विरोध करने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव की स्थापना की और सबसे पहले पुणे के शनिवारवाड़ा मे गणपति उत्सव का आयोजन किया गया। देश की आजादी के आन्दोलन में गणेश उत्सव ने बहुत महत्वपूण भूमिका निभायी थी। 1894 मे अंग्रेजो ने भारत मे एक कानून बना दिया था जिसे धारा 144 कहते हैं जो आजादी के इतने वर्षों बाद आज भी लागू है। इस कानून मे किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते थे। और ना ही समूह बनाकर कहीं प्रदर्शन कर सकते थे।

1894 से पहले लोग अपने अपने घरो मे गणपति उत्सव मनाते थे। लेकिन 1894 के बाद इसे सामूहिक तौर पर मनाने लगे। पुणे के शनिवारवडा के गणपति उत्सव मे हजारो लोगो की भीड़ उमड़ी। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजो को चेतावनी दी कि हम गणपति उत्सव मनाएगे अंग्रेज पुलिस उन्हे गिरफ्तार करके दिखाये। कानून के मुताबिक अंग्रेज पुलिस किसी राजनीतिक कार्यक्रम मे एकत्रित भीड़ को ही गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन किसी धार्मिक समारोह मे उमड़ी भीड़ को नहीं।

20 अक्तूबर 1894 से 30 अक्तूबर 1894 तक पहली बार 10 दिनो तक पुणे के शनिवारवाड़ा मे गणपति उत्सव मनाया गया। लोक मान्य तिलक वहां भाषण के लिए हर दिन किसी बड़े नेता को आमंत्रित करते। 1895 मे पुणे के शनिवारवाड़ा मे 11 गणपति स्थापित किए गए। उसके अगले साल 31 और अगले साल ये संख्या 100 को पार कर गई। फिर धीरे -धीरे महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरो अहमदनगर, मुंबई, नागपुर, थाणे तक गणपति उत्सव फैलता गया। गणपति उत्सव में हर वर्ष हजारो लोग एकत्रित होते और बड़े नेता उसको राष्ट्रीयता का रंग देने का कार्य करते थे। इस तरह लोगो का गणपति उत्सव के प्रति उत्साह बढ़ता गया और राष्ट्र के प्रति चेतना बढ़ती गई।

1904 में लोकमान्य तिलक ने लोगो से कहा कि गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य हासिल करना है। आजादी हासिल करना है और अंग्रेजो को भारत से भगाना है। आजादी के बिना गणेश उत्सव का कोई महत्व नहीं रहेगा। तब पहली बार लोगो ने लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को बहुत गंभीरता से समझा। आजादी के आन्दोलन में लोकमान्य तिलक द्वारा गणेश उत्सव को लोकोत्सव बनाने के पीछे सामाजिक क्रान्ति का उद्देश्य था। लोकमान्य तिलक ने ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों की दूरी समाप्त करने के लिए यह पर्व प्रारम्भ किया था जो आगे चलकर एकता की मिसाल बना।

भगवान गणेश ने बिना रुके दस दिनों तक महाभारत लिखी। इस दौरान एक ही स्थान पर लगातार लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई थी। दसवें दिन गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। तभी से गणेश उत्सव के दसवें दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है।

लोकमान्य तिलक ने जिस उद्देश्य को लेकर गणेश उत्सव को प्रारम्भ करवाया था वो उद्देश्य आज कितने सार्थक हो रहें हैं। आज के समय में पूरे देश में पहले से कहीं अधिक धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाये जाते हैं। मगर आज गणेशोत्सव में दिखावा अधिक नजर आता है। आपसी सदभाव व भाईचारे का अभाव दिखता है। आज गणेश उत्सव के पण्डाल एक दूसरे के प्रतिस्पर्धात्मक हो चले हैं। गणेशोत्सव में प्रेरणाएं कोसों दूर होती जा रही हैं और इनको मनाने वालों में एकता नाम मात्र की रह गयी है। इस बार हमें एक बार फिर से संगठित होकर गणेशोत्सव को इतनी ख़ुशी व धूमधाम से मनाना चाहिए जिससे समाज मे एकता व भाईचारा बढ़ सकें। सही मायने में तभी हमारी पूजा सार्थक हो सकेगी।

रमेश सर्राफ धमोरा

गणेश चतुर्थी व्रत से होती है शुभ फलों की प्राप्ति

प्रज्ञा पाण्डेय

अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर ला रहे हैं या स्थापना करते रहते हैं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिष विद्या के अनुसार, भगवान की मूर्ति सही दिशा में व सही विधि से स्थापित करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

आज गणेश चतुर्थी है, इस दिन से गणेश उत्सव शुरू हो जाता है। गणपति जी के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। दस दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है, तो आइए हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की विधि एवं महत्व के बारे में बताते हैं।

इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। देशभर में पूरे 10 दिनों तक गणपति उत्सव की धूम रहती है। इस दौरान भक्त बप्पा की भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते हैं और हर गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्तगण बप्पा की प्रतिमा को घर लाते हैं और विधिपूर्वक, नियम के साथ इसकी स्थापना करते हैं। गजानन जी की प्रतिमा घर में पूरे 10 दिनों तक रखा जाता है लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं तो 1, 3,5, 7 या 10 दिन तक गणेश जी को घर में विराजमान कर सकते हैं। गौरीपुत्र गणेश की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बनी रहती है। अगर आप अपने घर में गणपति जी को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो रोजाना उनकी पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं।

मूर्ति स्थापना करते समय दिशा का रखें ध्यान

अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर ला रहे हैं या स्थापना करते रहते हैं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिष विद्या के अनुसार, भगवान की मूर्ति सही दिशा में व सही विधि से स्थापित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति को घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। यदि ईशान कोण में रिक्त स्थान उपलब्ध ना हो तो मूर्ति को पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं।

गणेश चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त

भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि आरंभ- 6 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 1 मिनट से

भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि समाप्त- 7 सितंबर को शाम 5 बजकर 37 मिनट तक

गणेश चतुर्थी तिथि- शनिवार, 7 सितंबर 2024

गणेश विसर्जन तिथि- मंगलवार, 17 सितंबर 2024

गणेश चुतर्थी के दिन इस समय करें पूजा, मिलेगा लाभ

हिंदू पंचांग के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 3 मिनट से शुरू होगा, जबकि इसका समापन दोपहर 1 बजकर 34 मिनट पर होगा। भक्तगण इसी मुहूर्त में गणपति जी मूर्ति को अपने घर में स्थापित करें। गजानन जी की मूर्ति विधिपूर्वक ही स्थापित करें। वहीं गणेश जी की वो मूर्ति ही घर लाएं जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर हो।

गणेश चतुर्थी पर न देखें चंद्रमा

गणेश चतुर्थी के दिन भाद्रपद की विनायक चतुर्थी है। इस दिन आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर झूठा कलंक लग सकता है। भगवान श्रीकृष्ण पर मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। इसकी कथा चतुर्थी से जुड़ी है।

रवि और ब्रह्म योग में होगी गणेश चतुर्थी पूजा

इस साल गणेश चतुर्थी की पूजा रवि और ब्रह्म योग में होगी। चतुर्थी के दिन रवि योग सुबह 06:02 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक है, वहीं ब्रह्म योग सुबह से लेकर रात 11:17 बजे तक है।

अभिजीत मुहूर्त में करें गणपति स्थापना

गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना आप अभिजीत मुहूर्त में करें। यह घट और मूर्ति स्थापना के लिए अच्छा समय माना जाता है। उस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:54 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक है।

मूर्ति स्थापना के लिए आवश्यक पूजा सामग्री

पंडितों के अनुसार भगवान गणेश को विराजित करने के लिए चौरंगा या पाटा और रखने के लिए वस्त्र रखें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री हैं निरंजन, धूप, समई, कपूर और आरती की थाली। पांच फल, सुपारी, नारियल, पान के पत्ते, सूखा नारियल, गुड़ और कुछ सिक्के। पूजा स्थल पर रखने के लिए क्लश, जल और आम के पत्ते जरूर रखें।

साइबरशाला : डिजिटल डाइटिंग : डॉ. अंकुर शरण

साइबरशाला द्वारा आयोजित विशेष साक्षात्कार: साइबर विशेषज्ञ डॉ. वैभव सरन और सुश्री मृणालिनी सिंह से श्डिजिटल डाइटिंगश् पर चर्चा

डॉ. अंकुर शरण: आज के इस विशेष साक्षात्कार में आपका स्वागत है, जहाँ हम श्डिजिटल डाइटिंगश् के महत्व पर चर्चा करेंगे और यह मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे साथ साइबर विशेषज्ञ डॉ. वैभव सरन और सुश्री मृणालिनी सिंह हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप दोनों का स्वागत है।

डॉ. वैभव : धन्यवाद, डॉ. शरण। इस महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनने का अवसर पाकर मैं प्रसन्न हूँ।

सुश्री मृणालिनी सिंह: मुझे इस विषय पर चर्चा करने का उत्साह है। आज की डिजिटल दुनिया में संतुलित डिजिटल जीवन जीना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

डॉ. अंकुर शरण: सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि श्डिजिटल डाइटिंगश् क्या है? हमारे कई दर्शकों के लिए यह एक नया विषय हो सकता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है?

डॉ. वैभव : बिल्कुल। डिजिटल डाइटिंग एक ऐसा विचार है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की तरह काम करता है, लेकिन इसका संबंध हमारे डिजिटल कंटेंट की खपत से है। जिस तरह हम अपने खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना समय ऑनलाइन बिता रहे हैं, किस प्रकार की सामग्री देख रहे हैं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर कैसे सहभागिता कर रहे हैं। डिजिटल सामग्री की अत्यधिक खपत या गलत प्रबंधन से चिंता, अवसाद और सामाजिक अलगाव जैसी मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सुश्री मृणालिनी सिंह: इसके साथ ही, डिजिटल डाइटिंग में संतुलन और सचेत भागीदारी पर ज़ोर दिया जाता है। हम अक्सर यह नजरअंदाज कर देते हैं कि निरंतर कनेक्टिविटी और सूचनाओं की भरमार हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब हम अपनी डिजिटल सामग्री का चयन करते हुए सीमाएं तय करते हैं, तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है, जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं।

डॉ. अंकुर शरण: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी बढ़ती भूमिका के बारे में आप क्या सलाह देंगे कि लोग अपने दैनिक जीवन में डिजिटल डाइटिंग कैसे लागू कर सकते हैं?

सुश्री मृणालिनी सिंह: यह सब संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। अपने ऑनलाइन कार्यों के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और उन्हें नियमित रूप से अपनाएँ। उदाहरण के लिए, सुबह और शाम एक-एक घंटे सोशल मीडिया देखने के लिए तय करें। इसके अलावा, बाकी समय में ऑफलाइन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने डिजिटल वातावरण को बेहतर बनाएँ—ऐसे खातों को अनफॉलो करें जो तनाव या नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं और उन लोगों का अनुसरण करें जो आपको प्रेरित करते हैं।

डॉ. वैभव : इसके साथ ही, नियमित रूप से डिजिटल डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है। यह एक दिन के लिए सभी डिजिटल उपकरणों से दूर रहने जितना सरल हो सकता है, या हर दिन कुछ समय के लिए पूरी तरह से स्क्रीन से दूर रहना। ऐसी गतिविधियों में संलग्न हों, जो तकनीक से मुक्त हों, जैसे किताब पढ़ना, व्यायाम करना, या प्रकृति के बीच समय बिताना। इन ब्रेक्स से डिजिटल थकान कम होती है और मानसिक स्पष्टता में सुधार आता है।

डॉ. अंकुर शरण: अब जब हम डिजिटल डाइटिंग के फोरेंसिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो साइबर सुरक्षा इसमें कैसे शामिल होती है?

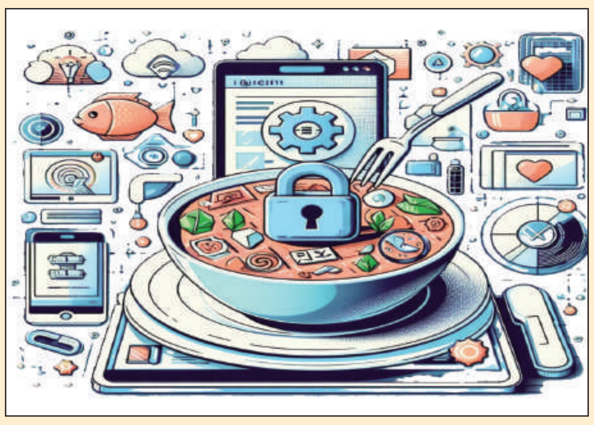

डॉ. वैभव : फोरेंसिक दृष्टिकोण से देखें, तो डिजिटल डाइटिंग में साइबर सुरक्षा का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम अपने खाने के प्रति सतर्क रहते हैं, उसी तरह हमें ऑनलाइन साझा की जाने वाली जानकारी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। इसमें मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना, फ़िशिंग घोटालों से सावधान रहना और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के परिणामों को समझना शामिल है।

सुश्री मृणालिनी सिंह: इसके अलावा, डिजिटल गोपनीयता के बारे में खुद को शिक्षित करना और इसे संरक्षित करने वाले कानूनों की जानकारी होना भी आवश्यक है। जागरूक होने से लोग डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और ज़िम्मेदारी से चल सकते हैं, जिससे साइबर खतरों का जोखिम कम हो जाता है। आज के जुड़े हुए समाज में साइबर सुरक्षा को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखना।

डॉ. अंकुर शरण: डिजिटल डाइटिंग का यह व्यापक दृष्टिकोण—जिसमें मानसिक, सामाजिक और साइबर सुरक्षा शामिल हैं—वास्तव में अत्यंत जानकारीप्रद है। अंत में, क्या आप हमारे दर्शकों को कोई अंतिम सुझाव देना चाहेंगे?

सुश्री मृणालिनी सिंह: मेरा सुझाव है कि आप अपने डिजिटल उपभोग को उसी सतर्कता से संभालें जैसे आप अपने शारीरिक आहार को संभालते हैं। सचेत रहें, चयनात्मक रहें, और हमेशा अपने कल्याण को प्राथमिकता दें। याद रखें, यह डिजिटल तकनीक को पूरी तरह से बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा संतुलन खोजने के बारे में है जो आपके लिए काम करता हो।

डॉ. वैभव : बिल्कुल। जुड़ा रहना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह से कि यह आपके जीवन को समृद्ध करे न कि उसे प्रभावित करे। अच्छी डिजिटल आदतें अपनाएँ, नियमित ब्रेक लें और जिस सामग्री के साथ आप जुड़ते हैं उसके बारे में सचेत रहें। आपका मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य इसके लिए आपको धन्यवाद देगा।

डॉ. अंकुर शरण: धन्यवाद, डॉ. वैभव और सुश्री मृणालिनी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके अमूल्य विचार साझा करने के लिए। आपकी जानकारी और सलाह हमारे दर्शकों को स्वस्थ डिजिटल आदतें अपनाने और अपने मानसिक, सामाजिक और ऑनलाइन स्वास्थ्य की रक्षा करने में अवश्य सहायता करेंगी।

यह साक्षात्कार डिजिटल खपत के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को रेखांकित करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके, हम डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और जागरूकता से संभाल सकते हैं।

साइबरशाला #Cybershala एक विशेष पहल है, जहाँ साइबर विशेषज्ञ छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे, जिससे लोगों में बेहतर साइबर जागरूकता फैलाई जा सके। यह वैश्विक गैर-सरकारी संगठनों के गठबंधन और साइबरशाला के संयुक्त प्रयास का हिस्सा है। इस पहल के माध्यम से, लोगों को साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की जानकारी दी जाएगी। डॉ. अंकुर शरण, जो Global Confederation of NGOs के मैनेजमेंट ट्रस्टी और सह-संस्थापक हैं, साइबर विशेषज्ञ डॉ. वैभव सरन इस जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि एक सुरक्षित और जागरूक डिजिटल समाज का निर्माण हो सके।

यात्रियों को नहीं मिल पा रहा दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड, एनसीएमसी कार्ड खरीदने के लिए मजबूर लोग

दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर यात्रियों को किराया भुगतान के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। इसकी जगह अब एनसीएमसी कार्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनसीएमसी कार्ड से न सिर्फ मेट्रो में बल्कि देशभर के सभी मेट्रो और गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड रेल में भी किराया भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा एनसीएमसी कार्ड से किराया भुगतान खरीददारी और बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर यात्रियों को किराया भुगतान के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। स्टेशनों के कस्टमर केयर काउंटर पर कर्मचारी जवाब देते हैं कि यह कार्ड अब उपलब्ध नहीं है। एक निजी निजी पेमेंट बैंक द्वारा स्टेशनों पर यात्रियों को एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) उपलब्ध कराया जा रहा है। कई यात्री न चाहते हुए भी यह कार्ड खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इस बाबत कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से शिकायत की है।

डीएमआरसी ने स्मार्ट कार्ड की तुलना में एनसीएमसी को बेहतर विकल्प बताया है, क्योंकि इससे देश भर के सभी मेट्रो और गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड रेल में भी किराया भुगतान किया जा सकता है। केंद्र सरकार भी एक देश एक कार्ड के रूप में एनसीएमसी को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में धीरे-धीरे स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कम होगा और एनसीएमसी को बढ़ावा मिलेगा।

सोशल मीडिया पर कारण पूछ रहे यूजर्स

अभिषेक नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा कि मेट्रो के स्मार्ट कार्ड क्यों नहीं मिल रहे हैं। वह एयरटेल का एनसीएमसी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जिस तरह पेटीएम का एनसीएमसी बंद हो गया उसी तरह यह भी बंद होने का डर है। यात्रियों को अधिक विकल्प दिया जाना चाहिए। धीरज कुमार नामक एक अन्य यात्री ने यह कार्ड रिचार्ज करने के बाद तुरंत अपडेट नहीं होने की शिकायत की। कई अन्य यात्रियों ने भी ऐसी शिकायतें की है।

सिर्फ पुराने कार्ड को दिक्कत आने पर बदले जा रहे

रेड लाइन के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर काउंटर पर पूछने पर डीएमआरसी के कर्मचारी ने बताया कि स्मार्ट कार्ड नहीं आ रहा है। ब्लू लाइन के उत्तम नगर पूर्व मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर पर भी यही जवाब मिला। आईटीओ स्टेशन के कस्टमर केयर के कर्मचारी ने बताया कि नए यात्रियों को स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करने का निर्देश है। जिन यात्रियों के पास पहले से स्मार्ट कार्ड हैं, यदि उसमें कोई दिक्कत होने पर पुराने कार्ड बदले जा रहे हैं।

एनसीएमसी कार्ड के हैं कई फायदे

डीएमआरसी का कहना है कि एनसीएमसी से यात्रियों को किराया भुगतान, खरीददारी, बैंकिंग सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जबकि स्मार्ट कार्ड से सिर्फ मेट्रो में किराया भुगतान हो पाता है। फिर भी कोई यात्री स्मार्ट कार्ड लेना चाहे तो मेट्रो स्टेशनों से खरीद सकता है। हर रोज करीब 12 हजार कार्ड बिक रहे हैं, जिसमें एनसीएमसी व स्मार्ट कार्ड दोनों शामिल होते हैं। मेट्रो में किराया भुगतान के लिए सभी बैंकों द्वारा जारी एनसीएमसी मान्य है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के मोबाइल एप से क्यूआर कोड टिकट सहित किराया भुगतान के कई अन्य विकल्प मौजूद हैं।

नरेला में बनेगी चौथी जेल, 2000 कैदियों की होगी क्षमता; खूंखार अपराधियों के लिए किया जा रहा तैयार

दिल्ली के नरेला में हाई सिक्योरिटी जेल के साथ एक नई केंद्रीय जेल का निर्माण किया जाएगा। 250 कैदियों की क्षमता वाली हाई सिक्योरिटी जेल के अलावा नई केंद्रीय जेल में 2000 कैदियों को रखने की जगह होगी। इस जेल के निर्माण का लक्ष्य दो वर्ष के भीतर रखा गया है। तिहाड़ रोहिणी और मंडोली के बाद नरेला दिल्ली का चौथा जेल परिसर होगा।

पश्चिमी दिल्ली। नरेला में अब हाई सिक्योरिटी जेल के साथ एक केंद्रीय जेल भी बनाया जाएगा। हाई सिक्योरिटी जेल में जहां 250 कैदी रहेंगे, वहीं नए केंद्रीय जेल में दो हजार कैदियों को रखने की जगह होगी। करीब दो वर्ष के भीतर इस जेल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नए केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

तिहाड़, रोहिणी और मंडोली के बाद नरेला में दिल्ली के चौथे जेल परिसर के निर्माण की मूल योजना के तहत यहां हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण होना था। इस जेल में उन खूंखार अपराधियों या कैदियों को रखा जाना है, जो गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं या सजायाफ्ता हैं या फिर जिनकी सुरक्षा काफी संवेदनशील होती है। हाई सिक्योरिटी जेल की क्षमता 250 कैदियों की है।

योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल चुकी

जेल प्रशासन के अनुसार नरेला में जेल निर्माण के लिए जितनी जगह मिली, वह इतनी है कि हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण के बाद भी काफी जगह खाली बच रही है। इस खाली जगह का इस्तेमाल करते हुए अब यहां एक केंद्रीय जेल के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इस योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। सबकुछ सही रहा तो हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण के साथ ही यहां नया केंद्रीय जेल भी बनना शुरू हो जाएगा।

समस्या का होगा करीब 20 प्रतिशत समाधान

तिहाड़ में अभी करीब 20 हजार कैदी बंद हैं, जबकि क्षमता करीब 10 हजार की है। नया केंद्रीय जेल बनने के बाद यहां दो हजार कैदी स्थानांतरित हो जाएंगे। इस लिहाज से देखें तो क्षमता से अधिक कैदी की समस्या से जूझ रहे तिहाड़ जेल की समस्या का करीब 20 प्रतिशत तक समाधान हो जाएगा।

विधायक अमानतुल्लाह खान की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा मुख्यालय पर "आप" का जबरदस्त प्रदर्शन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अवैध गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़क पर दिखा। ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग और "आप" नेताओं की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपने पुराने कार्यालय से प्रदर्शन करने जा रहे "आप" कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर भाजपा कार्यालय से पहले ही रोक दिया, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी कर अमानतुल्लाह खान को रिहा करने की मांग की। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए साम, दाम, दंड, भेद के हथकंडे अपनाती है। उसने मुझे, अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कई नेताओं के बाद अब अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कराया है, लेकिन "आप" तानाशाह हुक्मरानों के आगे न कभी झुकी है और न झुकेगी।

बीते सोमवार को ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने वक्फ बोर्ड के एक फर्जी मामले में अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ राउज एवेन्यू स्थित भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंची। इससे पहले पार्टी के विधायक, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने पूराने कार्यालय पर एकत्र हुए और यहां से 'ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, "आप" नेताओं की अवैध गिरफ्तारी बंद करो, ईडी-सीबीआई की मनमानी नहीं चलेगी' समेत अन्य नारे लगाते हुए भाजपा मुख्यालय की ओर कूच किए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दिलीप पांडे, मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के साथ विधायक राजेश गुप्ता, रितुराज झा, कुलदीप कुमार, अजेश यादव, हाजी यूनूस, मुकेश अहलावत, अजय दत्त, सुरेंद्र पहलवान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता में रहने के लिए भाजपा साम, दाम, दंड, भेद के हथकंडे अपनाती है। पहले पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है और जब पार्टी के लोग नहीं टूटते तो नेताओं के पीछे सरकारी एजेंसी को लगा देती है। ऐसा करके भारत के कई राज्यों में पार्टियों को तोड़कर सरकारें बनाई हैं। इसी कड़ी में मुझे, अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कई नेताओं के बाद अब विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया। मगर आम आदमी पार्टी तानाशाह हुक्मरानों के आगे न कभी झुकी है, न झुकेगी। हम भारत और संविधान के अस्तित्व को बचाने के लिए आखरी सांस तक लड़ते रहेंगे।

इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी की राजनीति जगजाहिर है। सीबीआई ने 2016 में तथाकथित वक्फ बोर्ड घोटाले में केस दर्ज किया, लेकिन 6 साल तक अमानतुल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया और कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। 6 साल बाद सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि इस मामले में कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसके बाद भी भाजपा ने इस मामले को एक बार फिर आधार बनाकर अपनी ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया और एक फर्जी केस दर्ज करवा दिया। इससे पहले इसी मामले में एसीबी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि इसमें कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यानी दो-दो बार भाजपा की कोशिश नाकाम हुई और उसके सियासी अहंकारी चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भाजपा रुकी नहीं और उसने ईडी को फिर से पीछे लगा दिया।

दिलीप पांडे ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने ईडी के कई नोटिस का जवाब दिया, उनके बुलाने पर गए और जब किसी कारण से नहीं जा पाए, तो लिखित में ईडी को न आने का कारण बताया। अमानतुल्लाह खान की सास का कैंसर का इलाज चल रहा है और कुछ दिनों पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है। इसलिए उन्होंने ईडी से कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन भाजपा और ईडी ने उनकी एक न सुनी और इस फर्जी मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा ने हर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया, संजय सिंह को चुनाव से पहले गिरफ्तार करके 6 महीने जेल में रखा गया, विजय नायर 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं, लेकिन उनकी जमानत भी जल्द होगी। भाजपा के अंदर आम आदमी पार्टी का डर है। वे चुनावी मैदान में हमारे सामने टिक नहीं पाते और अरविंद केजरीवाल जैसी नीतियां अपने किसी भी राज्य में नहीं ला पाते हैं। भाजपा का मकसद केवल अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमारे काम रोकना और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। लेकिन यह देश तानाशाही से नहीं, लोकतंत्र से चलेगा।

जिन्हें लगता है कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो उनमें से बहुत से लोग चुनाव के समय पाला बदलते हैं- कुलदीप कुमार

सुषमा रानी

नई दिल्ली। सितंबर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम के पार्टी छोड़ने को आम आदमी पार्टी ने एक समान्य घटना बताया। "आप" के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राजनीति है और राजनीति में लोगों का आना-जाना लगा रहता है। आम आदमी पार्टी ने उनको मंत्री बनाया था। उनको इसके आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकमनाएं हैं। वैसे भी जब चुनाव आते हैं और जिन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, तब उनमें से बहुत से लोग पाला बदलते ही है। हर पार्टी में चुनाव के समय टिकट कटने पर दो चार लोग पार्टियां बदल लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

आम आदमी पार्टी के सीमापुरी से विधायक एवं पूर्व मंत्री नेता राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का आना-जाना लगा रहता है। लोग पाला बदलते हैं, आते हैं-जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को पूरा सम्मान दिया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था। कुलदीप कुमार ने आगे कहा कि जब चुनाव आता है और किसी को लगता है कि उनका टिकट कट जाएगा, तब उस समय लोग पाला बदल लेते हैं। चुनाव के समय में यह सब चलता रहता है। उनके नए राजनीतिक जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वो खुश रहें, स्वस्थ्य रहें और उनका जीवन अच्छा चले।

आईपीएस अधिकारी ने दिखाया बड़ा दिल, घायल बाइक सवार को पहुंचाया अस्पताल; खुद उठाया पूरा खर्चा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त शशांक जायसवाल ने महिपालपुर बाईपास पर गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया और उसके इलाज का खर्च उठाने की पेशकश की। अनिल कुमार नामक बाइक सवार दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत हैं और एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। आईपीएस जायसवाल ने उन्हें ऑटो में बैठाकर स्पाइनल इंजरी सेंटर पहुंचाया और डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया।

नई दिल्ली। दिल्ली जैसे शहर में जहां लोग सड़कों पर घायल राहगीरों को देख किनारा कर लेते हैं, वहीं यहां ऐसे भी अधिकारी हैं जो घायल व्यक्ति को न सिर्फ अस्पताल पहुंचाते हैं बल्कि उसके उपचार में आए खर्च को भी उठाने को तैयार होते हैं। ऐसा ही एक मामला महिपालपुर बाईपास के पास देखने को मिला, जहां गंभीर रूप से घायल बाइकसवार को सड़क पर पड़ा देख आइपीएस शशांक जायसवाल मदद को आगे आए और उन्होंने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाते हुए उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया और उसके उपचार में आए खर्च की भी पेशकश की।आईपीएस शशांक जायसवाल यातायात पुलिस में उपायुक्त हैं। जानकारी के मुताबिक, रंगपुरा के रहने वाले अनिल कुमार दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत हैं। सोमवार रात करीब आठ बजे वह महिपालपुर बाईपास से गुजर रहे थे तभी टायर के नीच बजरी आने से उनकी बाइक फिसल गई और वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। सड़क पर खड़े लोग मूकदर्शक बनकर उसे देख रहे थे कि तभी पीछे से आईपीएस शशांक जायसवाल अपनी गाड़ी से उतरकर फरिश्ता बनकर आगे आए और घायल को ऑटो में बैठाया और खुद भी ऑटो में आगे बैठकर घायल को स्पाइनल इंजरी सेंटर ले गए।

मशहूर शायरा डॉ0 अना दहलनी के जन्मदिवस पर सोनम बेकर्स ने तैयार किया स्पेशल केक

सुषमा रानी

नई दिल्ली। फेस़ ग्रुप के चेयरमैन डॉ॰ मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व में विश्व प्रसिद्ध शायरा अना देहलवी के जन्म दिवस के मौके.पर एक म्यूजिकल गेट टू गेदर का आयोजन फेस़ स्टूडियों आराम पार्क में किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली सरकार के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान ने की। और क्षेत्रीय विधायक सुरेश कुमार बग्गा एडवोकेट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा कृष्णा नगर ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष गुरचरन सिंह राजू, डोलफिन फुटवियर के चेयरमैन सैय्यद फरहत अली, सोनम बेकर्स के डायरेक्टर हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, फिक्की के पेट्रन हाफिज़ सलीम अहमद, सियासी तक़दीर दैनिक के ग्रुप एडीटर मुस्तक़ीम खान, फ़ेस ग्रुप के मैनेजर डॉ॰ बिलाल अंसारी, आबी प्रोड्क्शन हाउस की मैनेजिंग डायरेक्टर शालू राठी, फैशन डिजाईनर श्वेता चुग, कांग्रेस नेता मौहम्मद अहमद, मुकेश शर्मा, मोईन जयपुरी, ख़ालिद ग़ाज़ी, एम॰ रामिश, इरफ़ान आज़ाद, खुर्शीद अहमद, फिक्की की फाइनेंस डायरेक्टर शबाना अज़ीम, आसिफ़ सैफ़ी, जैनब अंसारी, फरीद कुरैशी, इब्राहिम अली, मीनू ठाकुर, बॉबी आदि गणमान्य व्यक्तियों ने भी बर्थडे सेलीब्रेशन में शामिल होकर डॉ॰ अना देहलवी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मशहूर सिंगर वाजिद अली, इमेनुअल फ्रेंक, मेघा भारद्वाज, अभिषेक खंडेलवाल, कंचन चौधरी, रमेश झा व रोशन सुहेल आदि गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत पेश कर मेहमानों की वाहवाही लूटी। सभी गायकों ने बेहतरीन परफोरमेंस दी। मंच का संचालन मशहूर शायर दानिश अय्यूबी द्वारा किया गया।

सोनम बेकर्स ने स्पेशल केक इस अवसर के लिए तैयार किया था जिस पर डॉ॰ अना देहलवी की तस्वीर प्रिंट थी, मेहमानों ने सोनम बेकर्स के इस टैलेंट की काफी प्रशंसा कीं। केक कटिंग के बाद रात के खाने के साथ यह खूबसूरत यादगार प्रोग्राम सम्पन्न हुआ।

इस मौके पर विधायक सुरेश बग्गा ने कहा कि डॉ॰ अना देहलवी के जन्मदिवस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि डॉ॰ अना अपने टैलेंट के माध्यम से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। डॉ॰ मुश्ताक अंसारी ने कहा कि डॉ॰ अना के बर्थडे सेलीब्रेशन के पीछे एक कारण यह भी था कि डॉ॰ अना सभी को खुशियां बांटती हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी खुशियों में इज़ाफ़ा किया जाए। जाकिर खान ने कहा कि डॉ॰ अना देहलवी उर्दू अदब की दुनिया की महारानी हैं, देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दर्जनों मुल्कों में इनकी शायरी को पसंद किया जाता है, इनकी ख़ुशियों में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है।

केजरीवाल सरकार जेलों में बंद कैदियों की अस्वाभाविक मौत होने पर उनके परिजनों को ₹7.5 लाख का मुआवजा देगी

सुषमा रानी

नई दिल्ली, मानवाधिकारों के आदर्शों को मज़बूती प्रदान करते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिजनों या उनके कानूनी वारिसों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने के ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई, यातना, जेल अधिकारियों द्वारा लापरवाही, या चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण अप्राकृतिक मौत के मामलों में यह मुआवजा दिया जाएगा। वहीं आत्महत्या के कारण अप्राकृतिक मृत्यु, जेल से भागने के प्रयास या जेल के बाहर वैध हिरासत से या प्राकृतिक मृत्यु, आपदा या आपदा के मामलों में मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा यह बीमारी से होने वाली मौतों पर भी लागू नहीं होगा।

एक बयान में दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "यह पहल जेल प्रणाली के भीतर न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जेल में अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर कैदियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करना मानवाधिकारों के स्तंभों को मज़बूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार को विश्वास है कि इस क़दम से हमारी जेलों में सुधार होगा और किसी भी तरह की लापरवाही में कमी आएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।"

इस सिलसिले में संबंधित जेल अधीक्षक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट की एक प्रति, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु का अंतिम कारण, जेल में प्रवेश के समय चिकित्सा इतिहास और मौत से पहले प्रदान किए गए किसी भी चिकित्सा उपचार का विवरण शामिल होगा। यह रिपोर्ट सूचना हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को प्रस्तुत करने के लिए जेल महानिदेशक, दिल्ली को भेजी जाएगी। जेल महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें दिल्ली जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, डीसीए, और लॉ ऑफिसर होंगे, वो रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और नियमों के अनुसार मुआवजा जारी करने पर निर्णय लेंगे।

प्रस्ताव में समिति को हर तिमाही या आवश्यकतानुसार एक बार बैठक कर हिरासत में मौत के मामलों पर विचार करना आवश्यक है। मृतक के परिजनों को मुआवजा दे दिए जाने पर जेल महानिदेशक को एनएचआरसी को सूचित करना होगा।

नीति में दोषी जेल अधिकारियों के वेतन से मुआवजे की राशि की वसूली का भी प्रावधान है। इसके लिए समिति को जांच करनी होगी और यदि हिरासत में मौत में किसी जेल कर्मचारी की सीधी संलिप्तता पायी जाती है, तो समिति दोषी अधिकारी के वेतन से मुआवजा राशि की वसूली का आदेश, जैसा उचित समझती हो उस तरीके से दे सकती है।

नोएडा में 15 हजार फ्लैट खरीदारों से हुई धोखाधड़ी!

पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा में घर खरीदने से पहले पढ़ लें पूरी खबर। सुपरटेक की कई परियोजनाओं में बीते 14 सालों से 15 हजार से ज्यादा खरीदार अभी भी अपने फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसको लेकर लिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से शिकायत की गई है। जिसके बाद FIR दर्ज की गई। शिकायत में अधूरे घर महंगा बिजली और पानी का शुल्क अतिक्रमण आदि का भी जिक्र किया गया।

ग्रेटर नोएडा। सुपरटेक की अलग-अलग परियोजनाओं में बीते 14 सालों से 15 हजार से ज्यादा खरीदार फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को सुपरटेक परियोजनाओं के खरीदार पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मिले और बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। जिन लोगों को घर दिए गए हैं उनके लिए प्रबंधन से दी जा रही सुविधाओं का अभाव है।

पुलिस कमिश्नर से मिले फरीयादी

खरीदार अयोग रस्तोगी ने कहा कि सुपरटेक लिमिटेड की आठ आवासीय परियोजनाएं (noida flat buyers), नार्थ आई, इकोसिटी, रोमानो, केपटाउन, इकोविलेज-1, इकोविलेज-3, स्पोर्ट्स विलेज, अपकंट्री के घर खरीदारों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा।

कमिश्नर को बताया कि घर खरीदार सुपरटेक लिमिटेड और वाईजी एस्टेट के धोखाधड़ी के शिकार हैं। 2010 में सुपरटेक द्वारा शुरू की गई कई आवासीय परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं। आईआरपी हितेश गोयल की रिपोर्ट के अनुसार सुपरटेक लिमिटेड की आवासीय परियोजना में 15000 से अधिक घर खरीदार अभी भी अपने घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने को कहा

अधूरे घर, महंगा बिजली और पानी का शुल्क, अतिक्रमण समेत रखरखाव को लेकर तमाम असुविधाएं हैं। शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने खरीदारों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि घर खरीदार अपनी शिकायत को डीसीपी क्राइम को दर्ज करा सकते हैं।

जिस पर बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी। बीते महीने सुपरटेक की परियोजनाओं के खरीदार पुलिस मुख्यालय में ईओडब्ल्यू के विशेष आयुक्त शरद अग्रवाल से मुलाकात कर बिल्डर पर फंड में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जांच की मांग कर चुके हैं। इस दौरान गुलशन कुमार, चेतन कपूर, महेंद्र कुमार महिंद्रा, अचिन मजूमदार और समन्वय राउत्रे आदि मौजूद रहे।

सावधान! नोएडा में फिर सक्रिय हुआ एटीएम कार्ड बदलने वाला गिरोह; किन लोगों को बनाते हैं निशाना?

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा में एटीएम कार्ड बदलकर खाता खाली करने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। सेक्टर 24 में एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड को बदलकर उसके खाते से एक लाख रुपये उड़ा लिए गए। पीड़ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस ने कहा कि सावधान रहें और अपने एटीएम कार्ड को सुरक्षित रखें।

नोएडा। शहर में एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खाता खाली करने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड को बदलकर खाते से एक लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ति धर्मेंद्र ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़ित ने बताया कि वह गीझोड के पास एटीएम बूथ से पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान दो शातिर आये और बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। घर पहुंच कर मोबाइल पर मैसेज आए तो पीड़ति को बैंक खाते से पैसे निकालने का पता चला। पीड़ित ने बैंक और पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की।

उधर, पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। साइबर पुलिस का कहना है कि सावधान रहें और अपने खाते को सुरक्षित रखें। किसी तो भी अपना पिन व ओटीपी नंबर न बताएं।

शनिवार को नोएडा में होंगी राज्यपाल आनंदी बेन, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; घर से निकलने से पहले देखें रूट

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन शनिवार को ग्रेटर नोएडा दौरे पर आ रही हैं। यहां पर वह शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जिसको देखते हुए प्रशासन के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने भी राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सुबह नौ बजे से 11 बजे के बीच ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। पढ़ें इस दौरान आप किन मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन शनिवार को ग्रेटर नोएडा दौरे पर आ रही हैं। यहां पर वह शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जिसको देखते हुए प्रशासन के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने भी राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सुबह नौ बजे से 11 बजे के बीच ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। पढ़ें इस दौरान आप किन मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नोएडा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन शनिवार को ग्रेटर नोएडा के निजी शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगी। इस कारण नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह नौ बजे से 11 बजे के बीच ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा।

इन रास्तों का करें इस्तेमाल

गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से चूहडंपुर, आईएफएस विला, एक्सपो मार्ट गोलचक्कर, नासा गोलचक्कर से शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा तक व नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर परी चौक, जीरो प्वाइट (आगरा से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर उतरने वाला कट) हरनंदी कट, सेक्टर-152, 132, सेक्टर 128।

सेक्टर 126, सेक्टर 125 कट, चरखा गोलचक्कर, महामाया फ्लाईओवर, गन्दा नाला तिराहा, दलित प्रेरणा स्थल यू-टर्न, जीआईपी से दलित प्रेरणा स्थल की ओर उतरने वाला लूप, रजनीगंधा से डीएनडी टोल की ओर जाने वाले मार्ग के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से अल्प समय के लिए वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं मदद

डायवर्जन के समय आपातकालीन वाहनों को सकुशल गंतव्य को भेजा जाएगा। ऐसे में शहरवासी डायवर्जन प्लान को देखकर निकलें। डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद का कहना है कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। जानकारी के लिए यातायात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001, वाट्सएप नंबर 7065100100 एवं एक्स हैंडल @noidatraffic से संपर्क कर सकते हैं।

स्कूल में बच्ची से गंदी हरकत, हेड मिस्ट्रेस व ठेकेदार समेत 4 गिरफ्तार; मुख्य आरोपित की तलाश में जुटी पुलिस

नोएडा के एक निजी स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने हेड मिस्ट्रेस क्लास टीचर सुपरवाइजर और ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर घटना को छिपाने का आरोप है। मुख्य आरोपी कामगार अभी भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन कर चुकी है।

नोएडा। नोएडा में सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र के निजी स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ बैड टच के मामले में पुलिस ने हेड मिस्ट्रेस, क्लास टीचर, सुपरवाइजर व ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर घटना को छिपाने का आरोप है। मुख्यारोपित कामगार फरार है। उसके पकड़ने के लिए चार टीमें लगी हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय अरविंद कुमार ने बताया कि मंगलवार को निजी स्कूल में कामगार ने छह साल की बच्ची को गलत तरीके से छुआ था। उसके स्वजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई। पता चला कि बच्ची के साथ स्कूल परिसर निर्माण कार्य चल रहा है।

ठेकेदार ने आरोपित कामगार की भागने में की मदद

पुलिस के अनुसार, काम में लगे एक कामगार ने गलत बच्ची के साथ गलत हरकत की थी। बच्ची ने इसकी जानकारी हेड मिस्ट्रेस व क्लास टीचर को दी थी। स्कूल के सुपरवाइजर को भी इसकी जानकारी हुई। तीनों ने मामले को छिपा लिया। ठेकेदार ने आरोपित कामगार की भागने में मदद की।

वहीं, साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यारोपित की गिरफ्तारी के लिए लगीं चार टीमों में से एक टीम उसके गृह जनपद भी गई है। सीसीटीवी कैमरों व सर्विलांस की मदद ली जा रही है।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए यूपी का रास्ता अपनाना होगा

अशोक मधुप

अपराधियों और माफियाओं के विरूद्ध उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर चलाया। उनके द्वारा खड़ी की गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। ये प्रयोग इतना सफल रहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटे। अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने लगे।

आज आमजन भ्रष्टाचार पीड़ित है। ऐसा लगने लगा है कि कोई काम अब रिश्वत दिए बिना नहीं होता। भ्रष्टाचार देश की जड़ तक पहुंच गया। सभी इससे परेशान हैं किंतु इसके रोकने के लिए कोई पहल नही कर रहा। ईमानदारी का चोला पहन कर राजनीति में आई आम आदमी पार्टी खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। आप के सर्वे सर्वा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं दिल्ली के शराब घोटाले में जेल में हैं।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था की है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है हालांकि अभी इसमें बहुत कुछ करना होगा। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को पूरे देश को स्वीकारना होगा। भ्रष्टाचार करने वालों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश की कार्रवार्ई को अन्य प्रदेशों को अपने यहां लागू करना होगा, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में शुरूआत है। इस आदेश के परिणाम आने में समय लगेगा।

अपराधियों और माफियाओं के विरूद्ध उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर चलाया। उनके द्वारा खड़ी की गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। ये प्रयोग इतना सफल रहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटे। अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने लगे। प्रदेश की कामयाबी देख अन्य कुछ राज्यों ने भी यही बुलडोजर की कार्रवाई को स्वीकारा। इसे अपने यहां लागू किया। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक्शन की प्रशंसा की।

प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदेश में राज्य के आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया था। हालांकि शिक्षकों, निगम कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया। सरकार ने इसके लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए इसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। आदेश के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ये काम नहीं किया। इस कारण सरकार ने इनकी सैलरी रोकने का आदेश किया दी। पहले खबर आई थी इनका प्रमोशन भी रोका जा रहा है। अब यूपी सरकार ने कर्मचारियों को एक महीने का और वक्त दिया है। ये सरकार की ओर से आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मात्र 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड की है। 2,44,565 राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया।

उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्ति घोषित करें नहीं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी भी नहीं आएगी। सरकारी कर्मियों को संपत्ति घोषित करने का निर्देश पहले भी दिया जा चुका है लेकिन संतोषजनक रिस्पांस नहीं मिलने पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है।

यूपी सरकार ने अब राज्य कर्मचारियों को एक महीने की छूट दी है और आदेश दिया है कि कर्मचारी दो अक्तूबर तक संपत्ति का ब्योरा दे सकेंगे। पहले ब्योरा न देने वालों कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोकने का आदेश दिया गया था। संपत्ति का ब्यौरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे। जबकि, शिक्षा विभाग के कार्मिक अपनी संपत्ति को छिपाने में आगे हैं। इस लिहाज से सबसे फिसड्डी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग साबित हुए।

17 अगस्त को जब यह आदेश जारी हुआ था, तब 131748 यानी 15 फीसदी राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज की थी। 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गया। शासन के एक उच्चपदस्थ अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं। इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। विवरण दर्ज कराने के आदेश पर जीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर उनके कार्मिकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दिए जाने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिस कर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। माना जा रहा है कि गृह विभाग के लिए यह तिथि

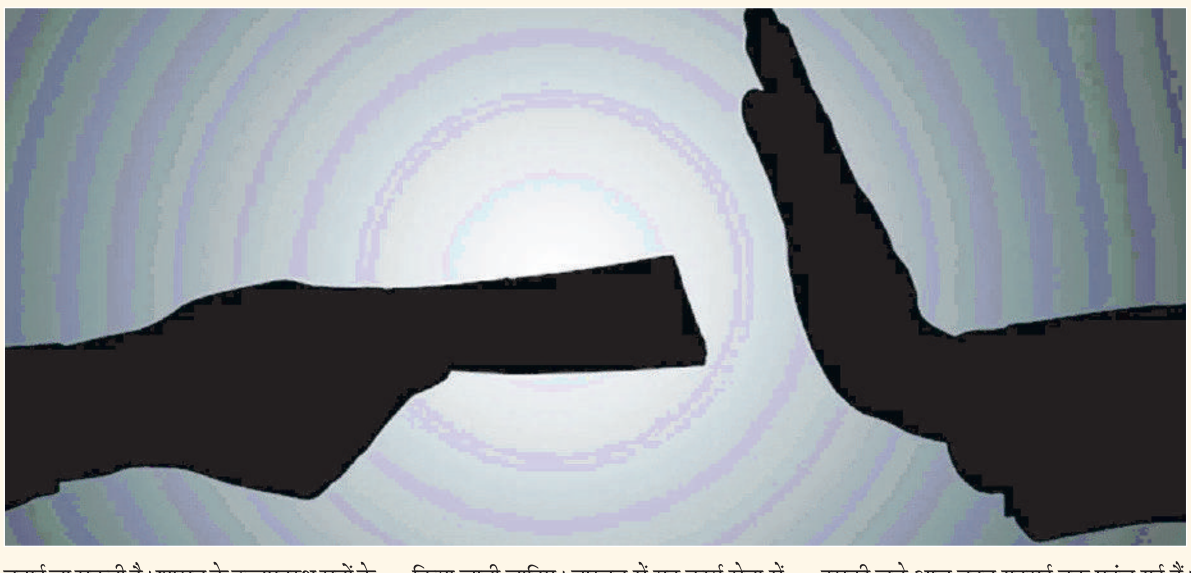

बढ़ाई जा सकती है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जिन अधिकारियों-कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया, इसे तभी जारी किया जाएगा, जब वे संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे। उनकी संपत्ति का ब्यौरा मिलने पर वेतन देने का फैसला संबंधित विभाग शासन से वार्ता के बाद ले सकेंगे। लगता है कि इसी पत्र के बाद विवरण दर्ज कराने के लिए एक माह का और समय दिया गया है।

आदेश सही है किंतु इसमें अभी सुधार करना होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ करना होगा। कर्मचारियों के अपनी चल और अचल संपत्ति के मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने से काम नही चलेगा। इसके लिए उसके परिवार के सभी सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा दर्ज कराना होगा। ये आदेश राज्य सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जानी चाहिए। वास्तव में यह कार्य सेवा में आने से पूर्व होना चाहिए। सेवा में आने के बाद शादी होने पर कर्मचारी अपनी पत्नी की प्रत्येक प्रकार की संपत्ति दर्ज कराए। बच्चे होने पर उनका विवरण दर्ज हो। इतना ही नही जन प्रतिनिधियों, जन सेवकों पर भी यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। आज हालत यह है कि देख गया है कि प्रधान या स्थानीय निकाय का चेयरमैन बनते ही उसके पास लंबी चौड़ी गाड़ी आ जाती है। यह तभी रूकेगी जब, उसके और उसके परिवार की चल अचल संपत्ति चुने जाते ही शपथ से पूर्व घोषित की जाए। विधायकों और विधान परिषद सदस्य, विभिन्न बोर्ड के पदाधिकारी और सदस्यों पर भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए।

समाज में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए देश को सख्त निर्णय लेने होंगे। भ्रष्ट हुई व्यवस्था अब बिना सख्ती के ठीक नही होगी। इसकी जड़े आज बहुत गहराई तक पहुंच गई हैं। भ्रष्टाचार की इन जड़ों को ही हमें नही काटना होगा, अपितु इनकी जड़ों का मिल रहा खाद पानी भी रोकना होगा। एक बात और कि ऐसी भी व्यवस्था कानून में होनी चाहिए की रिश्वत देने वाला सरकार को बताए कि उससे रिश्वत मांगी जा रही है। उसके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाए। सूचना पर कार्रवाई होने के बाद सूचना देने वाले को सम्मानित भी किया जाए। अगर नही बताता है तो पता चलने पर उसके विरूद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए।

एक चीज और हमें स्कूली शिक्षा से ही बच्चों को आदर्श नागरिक बनने के बारे में उसे बताना होगा। उसे प्रेरित करना होगा कि वह समझे कि भ्रष्टाचार गलत है। भ्रष्टाचारी के प्रति होने वाली कार्रवाई से भी उसे अवगत कराया जाए, ताकि बचपन से ही इस कुरूति के प्रति उसके मन में गलत धारणा बन सके। ऐसा होने पर ही इसे रोका जा सकेगा।

-:सौजन्य:-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

सुबह 09 से सायं 07 बजे तक अंबाला में बच्चे और महिलाएं फ्री में करेंगे ई-रिक्शा की सवारी

परिवहन विशेष न्यूज

बदलते समय के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति भी लगातार बदल रही है। आज के समय में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता है। इस दिशा में अंबाला के एक समाज सेवा संगठन ने महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त ई-रिक्शा सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं और बच्चे बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

नन्हे कदम ट्रस्ट नाम की यह संस्था खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए यह सेवा मुहैया करा रही है। महिलाओं के लिए यह सुविधा इसलिए शुरू की गई है ताकि वे सुबह काम पर जाते समय या घर लौटते समय बिना किसी खर्चे के आसानी से यात्रा कर सकें। इसके अलावा सुबह स्कूल जाते समय और छुट्टी के बाद घर लौटते समय बच्चों को भी इस मुफ्त ई-रिक्शा सेवा का लाभ मिल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि चिलचिलाती धूप में बच्चों को परेशानी न हो और वे सुरक्षित घर पहुंच सकें।

नन्हे कदम ट्रस्ट की संस्थापक पारुल नागपाल ने बताया कि अंबाला शहर में सुबह 09 बजे से शाम 07 बजे तक महिलाओं के लिए मुफ्त ई-रिक्शा सेवा शुरू की गई है। इसमें महिलाएं बिना किसी शुल्क के कहीं भी जा सकती हैं। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों के लिए यह सेवा भी उपलब्ध है, जिसमें ई-रिक्शा उन्हें मुफ्त में घर से स्कूल लाने और छुट्टी के बाद स्कूल से घर छोड़ने का काम करती हैं।

इस पहल के पीछे सोच यह है कि आज के समय में महिलाओं का समाज में अहम योगदान है और उनकी सुविधा के लिए इस तरह की सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी यह ई-रिक्शा सेवा पूरी तरह से मुफ्त है, जिससे उन्हें भी काफी फायदा मिल रहा है।

केंद्र सरकार फेम-3 के तहत इलेक्ट्रिक एंबुलेंस और पुलिस वाहनों के लिए प्रोत्साहन योजना पर कर रही विचार

परिवहन विशेष न्यूज

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार आगामी फेम 3 योजना के तहत इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। साथ ही अगर खरीदार पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं तो ईवी पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार फेम 3 सब्सिडी योजना के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन देने पर विचार कर रही है। यह संभव है कि केंद्र सरकार हर श्रेणी पर दो साल की अवधि में प्रोत्साहन कम कर सकती है।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को भी सब्सिडी का प्रमाण पत्र मिल सकता है और ओईएम के साथ इन प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को जारी करने की विधि पर चर्चा चल रही है।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 4 सितंबर को कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार दो महीने के भीतर फेम योजना के तीसरा संस्करण को अंतिम रूप दे देगी। योजना में इलेक्ट्रिक बसों, तीन पहिया वाहनों और दो पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन शामिल होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक ट्रक, ट्रैक्टर, खनन उपकरण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी नई श्रेणियां भी शामिल की जा सकती हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने से रोजगार सृजन होने के साथ-साथ फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।

लेकिन इन सबके बीच इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को खत्म किए जाने का संकेत देते हुए

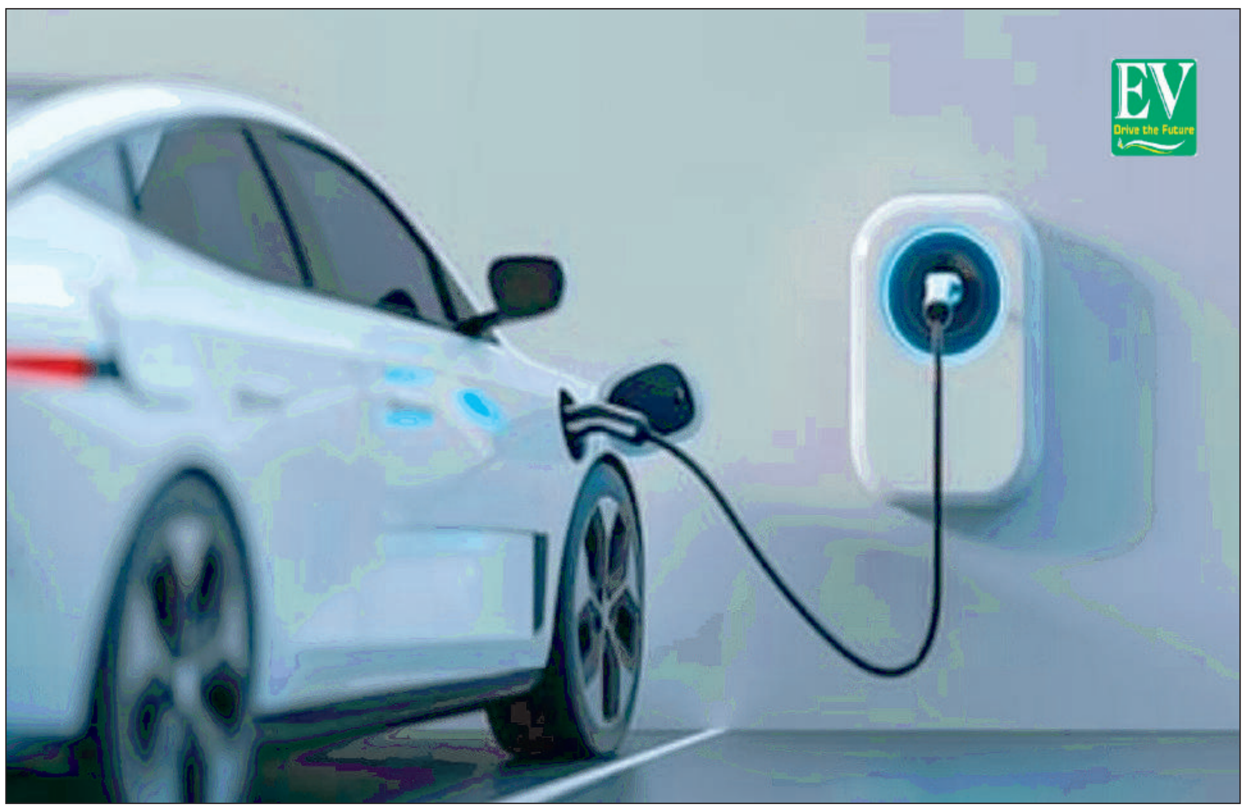

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार, 05 सितंबर को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता अब खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं।

बीएनईएफ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत ज्यादा थी। लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ी, उत्पादन लागत कम होती गई। जिससे आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं रह गई।

एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह फेम-3 योजना के लिए मिले इनपुट पर काम कर रहा है और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फेम योजना के पहले दो चरणों में मुद्दों को हल करने की कोशिश की जा रही है।

फेम 3 इससे समय लागू अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की जगह लेगा, जो सितंबर में समाप्त होने वाली है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ टेरा चार्ज ने की पार्टनरशिप

परिवहन विशेष न्यूज

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी टेरा चार्ज ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। कंपनी ने देशभर के एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा लगाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले भोपाल एयरपोर्ट से हुई है। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से पहली बार इस तरह की साझेदारी की गई है। इस करार के तहत देशभर के एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत भोपाल के राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई है।
जापानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भोपाल एयरपोर्ट पर 75 वर्ग मीटर के क्षेत्र में चार्जिंग सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसके ज़रिए एक बार में 4 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। शुरुआत में इस हब में स्लो चार्जर लगाया जाएगा। इसके अलावा 30 किलोवाट का फास्ट चार्जर भी दिया जाएगा, जो ई2व्हीलर, ई3व्हीलर और ई4व्हीलर की ज़रूरतों को पूरा करेगा।
इन पब्लिक और कमर्शियल चार्जर का इस्तेमाल 24 घंटे किया जा सकेगा। टेरा चार्ज पहली कंपनी है जिसने इस सेक्टर के लिए एएआई के साथ समझौता किया है। भोपाल के बाद अलग-अलग एयरपोर्ट पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
कंपनी ने 15 लाख रुपये का निवेश किया है और इसका लक्ष्य सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना है। इसके अलावा कंपनी के पास 4 और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हैं, जहां इस तिमाही के अंत तक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं।
कंपनी ने अभी तक कोई खास तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 45-60 दिनों में चार्जिंग स्टेशन लगा दिया जाएगा। एंड्रॉयड और आईओएस यूजर टेरा चार्ज मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग स्टेशन का पता लगा सकते हैं।

रोड टैक्स माफी वापस लेने के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट, कीमतों में 10% का उछाल

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत देश के कुछ अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बिक्री को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए ईवी पर रोड टैक्स पर दी जाने वाली छूट हटाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने दिल्ली ईवी नीति के हिस्से के रूप में यह लाभ पेश किया था। जिससे यात्री इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में चार पहिया और दो पहिया दोनों के लिए ईवी की लागत में 10 प्रतिशत की कमी आई थी। 31 अगस्त को ईवी नीति समाप्त हो गई, जिससे ईवी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और राष्ट्रीय राजधानी में बिक्री पर असर पड़ा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टैक्स बेनिफिट्स हटाने के बाद ईवी डीलरशिप पर इन्वेंट्री बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली ईवी नीति समाप्त होने के बाद ईवी की बिक्री प्रभावित हुई है। यह बात ऑटो डीलर्स बॉडी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सूत्रों के हवाले से बताया गया है। दिल्ली ईवी नीति बेनिफिट्स की वापसी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहन घर ले जाने के लिए 10 प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा, जो पहले माफ कर दिया गया था।

दिल्ली ईवी नीति, जिसे पिछले साल 31 दिसंबर को समाप्त होने के बाद दो बार बढ़ाया गया था, 7 अगस्त, 2020 को तीन साल की अवधि के लिए पेश की गई थी। राज्य सरकार ने अभी तक एक नई ईवी नीति को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिसकी जल्द ही समाप्त हो चुकी नीति की जगह लेने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 पर अभी भी चर्चा की जा रही है। जबकि इसे आकार देने

से पहले अधिसूचना के लिए अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा।

रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार, डीलर्स बॉडी और अन्य हितधारक राज्य सरकार के अधिकारियों से समाधान मांगने के लिए मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि सितंबर के पहले कुछ दिनों में ईवी की बिक्री में 'काफी' गिरावट आई है। सूत्रों में से एक ने कहा, ₹राज्य सरकार को ईवी पर रोड टैक्स छूट के विस्तार पर फैसला लेना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भले ही लाभ हासिल करने वाले वाहनों की संख्या पर सीमा तक नहीं पहुंची है। अगर मामले का जल्द समाधान नहीं हुआ तो अब तक हासिल हुए फायदों पर पानी फिर जाएगा।"

दिल्ली भारत के शहरों में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की सूची में दूसरे स्थान पर है। 2023 में, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के कुल 8,211 पंजीकरण देखे गए, जबकि बेंगलुरु ने 8,690 ईवी बिक्री के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इस साल जनवरी से मई के बीच, दिल्ली में सिर्फ 4,016 ईवी बिके हैं, क्योंकि सेगमेंट में कुल बिक्री में गिरावट आई है।

चीन की 'ईवी कॉलोनी' न बने भारत, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें: जीटीआरआई

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार को घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को प्रोत्साहनों पर निर्भरता के बिना स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना चाहिए क्योंकि इससे देश चीन के लिए 'ईवी कॉलोनी' बनने से बच जाएगा। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई ने शुक्रवार, 06 सितंबर को यह बात कही।

इसमें कहा गया है कि भारत को बड़े पैमाने पर ईवी को अपनाने में ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका सामना अन्य देशों को नहीं करना पड़ रहा है।

जीटीआरआई ने कहा कि इन चुनौतियों में कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न 80 प्रतिशत बिजली, बार-बार बिजली कटौती और देश में बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे ईवी बनाने के लिए जरूरी घटकों के लिए आयात पर निर्भरता शामिल है।

जीटीआरआई ने कहा, ''इन चुनौतियों पर विचार करते हुए भारी प्रोत्साहनों के साथ मैदान में उतरने या चीनी आयात पर निर्भर होने के बजाय भारत के पास अपने ईवी क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने का अवसर है। बाजार की ताकतों को क्षेत्र की वृद्धि को आगे बढ़ाने की अनुमति देकर, भारत चीन के लिए

'ईवी कॉलोनी' बनने से बच सकता है और वैश्विक ईवी परिदृश्य में अपना रास्ता बना सकता है।''

शोध संस्थान ने कहा कि वैश्विक ईवी बाजार में भूचाल आ रहा है, जिसकी वजह अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा द्वारा चीन से ईवी और उसके पुर्जों के आयात पर उच्च शुल्क और प्रतिबंध लगाना है।

ये क्षेत्र चीन के वैश्विक ईवी निर्यात का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं और एक रणनीतिक मोड़ में, चीन अपना उत्पादन आसियान देशों में स्थानांतरित कर रहा है और भारत पर अपनी नज़रें जमा रहा है।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, "ये उत्पादन इकाइयां अब भी चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहेंगी, क्योंकि बैटरी सहित 70-80 प्रतिशत पुर्जे वहीं से आते हैं। थाइलैंड चीनी कंपनियों को स्थानीय उत्पादन की अनुमति देने वाला पहला देश है, जो पहले से ही बढ़ते आयात और स्थापित विनिर्माताओं से कम बिक्री की शिकायतों के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि यह भी जोखिम है कि चीन भारत में अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन डाल सकता है, क्योंकि विकसित बाजारों तक उसकी पहुंच कठिन हो जाएगी।

अनिल अंबानी देंगे टाटा और महिंद्रा को कड़ी टक्कर, ईवी सेक्टर की बदलेगी सूरत

परिवहन विशेष न्यूज

अनिल अंबानी अब ईवी सेक्टर में उतरकर टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को टक्कर देने जा रहे हैं। इसके लिए अनिल अंबानी ने चीन की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बीवाईडी के पूर्व इंडिया हेड को सलाहकार नियुक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने की योजना पर विचार कर रही है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 250,000 वाहन प्रति वर्ष की शुरुआती क्षमता वाला ईवी प्लांट लगाने जा रही है और इसकी ₹लागत व्यवहार्यता₹ का अध्ययन करने के लिए बाहरी सलाहकारों को नियुक्त किया है। बाद में इस क्षमता को बढ़ाकर 750,000 किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी 10 गीगावाट-घंटे की बैटरी प्लांट की व्यवहार्यता पर भी विचार करेगी, जिसकी क्षमता आने वाले सालों में बढ़ाई जा सकती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और बीवाईडी के पूर्व कार्यकारी संजय गोपालकृष्णन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

मुकेश अंबानी की कंपनी पहले से ही स्थानीय स्तर पर बैटरी का निर्माण कर रही है और इस सप्ताह उसने 10 गीगावाट बैटरी सेल के उत्पादन के लिए सरकारी प्रोत्साहन के लिए बोलियाँ जीती हैं। यदि अनिल अंबानी का समूह अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो भाई ऐसे बाजार में प्रवेश करेंगे जहाँ ईवी की उपस्थिति कम है लेकिन वे तेजी से बढ़ रहे हैं।

रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर चीनी कंपनियों समेत दूसरे साझेदारों की भी तलाश कर रही है और कुछ महीनों में अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रही है। भारत की टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी ईवी कंपनी है जिसकी बाजार हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है। सैक SAIC की एमजी मोटर और बीवाईडी जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। दूसरी ओर, ऑटो बाजार की प्रमुख कंपनियों में शामिल मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर ने 2025 में ईवी लॉन्च करने की योजना बनाई है।

गोपालकृष्णन इस साल बीवाईडी से सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने बीवाईडी में दो साल से अधिक समय बिताया, कंपनी के स्थानीय व्यवसाय की स्थापना की, तीन ईवी लॉन्च किए और डीलरशिप नेटवर्क स्थापित किया।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जून में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऑटो से जुड़ी दो नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का गठन किया। एक का नाम रिलायंस ईवी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका ₹मुख्य उद्देश्य₹ ₹किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग करके परिवहन और परिवहन के लिए सभी प्रकार के वाहनों और घटकों का निर्माण और सौदा करना है।"

विजय गर्ग

ध्यान छात्रों की योग्यता, दृष्टिकोण और सफल होने की प्रेरणा के मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। परीक्षणों को मुक्त प्रवाह के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रश्न छात्र की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उत्पन्न होते हैं। यह दृष्टिकोण व्यापकता के स्थान पर ज्ञान की गहराई को प्राथमिकता देगा।

जेनरेटिव एआई और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियां भविष्य में एनईईटी और अन्य परीक्षाओं में हेरफेर को रोकने के लिए व्यवहार्य समाधान प्रदान करती हैं

पेपर लीक, हेरफेर और कुप्रबंधन की घटनाएं सिस्टम की अखंडता को कमजोर करती हैं और छात्रों पर दबाव डालती हैं। परीक्षा प्रक्रिया के महत्व को बनाए रखने में पारंपरिक तरीके त्रुटिपूर्ण साबित हो रहे हैं। यहीं पर प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में कदम रखती है। एनईईटी विवाद ने भारतीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे छात्रों को काफी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है। यह स्पष्ट है कि भविष्य में ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को हस्तक्षेप करना होगा। उन्नत तकनीकी समाधान आज उपलब्ध हैं जो इन कुप्रबंधन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं, फिर भी यथार्थवादी कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक बोर्डों और सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सबसे आशाजनक समाधानों में से एक एल्गोरिथम जनरेटिव एआई-आधारित तकनीक में निहित है। यह तकनीक सेट पेपर की अवधारणा को पूरी तरह खत्म कर सकती है। बिना सेट पेपर के प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना खत्म हो जाती है. हालाँकि, छात्रों को इन नई प्रौद्योगिकी समाधानों पर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, और पारंपरिक ओएमआर शीट से कंप्यूटर या टैबलेट-आधारित अंकन प्रणालियों में बदलाव आवश्यक है। व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत लाखों छात्रों के लिए एक निश्चित तारीख के बजाय SAT या GMAT जैसी प्रणाली अपना सकता है। यह प्रणाली छात्रों को डिजिटल और यादृच्छिक प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए अपनी सुविधानुसार परीक्षा देने की अनुमति देगी। ध्यान छात्रों की योग्यता, दृष्टिकोण और सफल होने की प्रेरणा के मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। परीक्षणों को मुक्त प्रवाह के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रश्न छात्र की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उत्पन्न होते हैं। यह दृष्टिकोण व्यापकता के स्थान पर ज्ञान की गहराई को प्राथमिकता देगा। पेशेवर क्षेत्र में कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण आवश्यक हैं। एक प्रणाली जो इन पहलुओं का आकलन करती है वह छोटे शहरों के छात्रों या उन लोगों के लिए नुकसान को प्रभावी ढंग से दूर करती है जो कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते। यह सब प्रौद्योगिकी के सही उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। एनईईटी विवाद भारतीय परीक्षा प्रणाली में एक प्रणालीगत समस्या को उजागर करता है। पेपर लीक, हेरफेर और कुप्रबंधन की घटनाएं सिस्टम की अखंडता को कमजोर करती हैं और छात्रों पर दबाव डालती हैं। परीक्षा प्रक्रिया के महत्व को बनाए रखने में पारंपरिक तरीके त्रुटिपूर्ण साबित हो रहे हैं। यहीं पर प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में कदम रखती है। एल्गोरिथम जनरेटिव एआई-आधारित समाधान जेनरेटिव एआई सेट पेपर की अवधारणा को खत्म करके परीक्षा प्रणाली में क्रांति ला सकता है। एआई एल्गोरिदम पूर्वनिर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर प्रत्येक छात्र के लिए अद्वितीय प्रश्न सेट बना सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी दो परीक्षण समान नहीं हैं। यह दृष्टिकोण प्रश्नपत्र लीक के जोखिम को काफी कम कर देता है और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त, एआई एक छात्र की प्रगति का विश्लेषण कर सकता है और व्यक्तिगत मूल्यांकन अनुभव प्रदान करते हुए वास्तविक समय में प्रश्नों के कठिनाई स्तर को अनुकूलित कर सकता है। इसके अलावा, एक लचीली प्रणाली जहां छात्र कई बार परीक्षा दे सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर चुन सकते हैं, उनके दबाव और चिंता को काफी कम कर सकता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को उनके भविष्य का निर्धारण करने वाली एकल, उच्च जोखिम वाली परीक्षा के डर के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, एआई-आधारित करियर काउंसलिंग को ऑनलाइन और व्यक्तिगत दोनों तरह से एकीकृत करने से छात्रों को उनके पाठ्यक्रमों और करियर पथों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिल सकता है। संभावित कैरियर विकल्पों में अंतर्दृष्टि प्रदान करके और उन्हें छात्र की रुचियों और क्षमताओं के साथ जोड़ते हुए, यह तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि छात्र न केवल अपनी परीक्षाओं के लिए बल्कि अपने भविष्य के प्रयासों के लिए भी अच्छी तरह से तैयार हों। प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन इन तकनीकी समाधानों को लागू करने के लिए छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ओएमआर शीट से डिजिटल मार्किंग सिस्टम में परिवर्तन में छात्रों को नए प्रारूप से परिचित कराना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि शिक्षक इन उपकरणों का उपयोग करने में कुशल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ इस अंतर को पाट सकते हैं, सभी हितधारकों को एक निर्बाध परिवर्तन के लिए तैयार कर सकते हैं। नीति और अनुमोदन व्यापक रूप से अपनाने के लिए, इन तकनीकी समाधानों को शैक्षिक बोर्डों और सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को प्रौद्योगिकी-संचालित परीक्षा प्रणाली के दीर्घकालिक लाभों को पहचानना चाहिए और इसके कार्यान्वयन की दिशा में काम करना चाहिए। इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों की इन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हो। डिजिटलीकृत परीक्षा प्रणाली की ओर आगे बढ़ना भारत में SAT/GMAT जैसी प्रणाली की परिकल्पना आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। ऐसी प्रणाली लचीलेपन की अनुमति देती है, जिससे छात्र अपनी सुविधानुसार परीक्षा दे सकते हैं। यह डिजिटलीकृत और यादृच्छिक दृष्टिकोण कदाचार की संभावना को कम करता है और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। योग्यता, दृष्टिकोण और कौशल पर ध्यान दें नई प्रणाली छात्रों की योग्यता, दृष्टिकोण और कौशल के मूल्यांकन को प्राथमिकता देगी। एआई-संचालित प्लेटफॉर्म पारंपरिक तरीकों की तुलना में इन गुणों का अधिक प्रभावी ढंग से आकलन कर सकते हैं। किसी छात्र के पिछले उत्तरों के आधार पर, उनकी क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुए, प्रश्न गतिशील रूप से उत्पन्न किए जा सकते हैं। समावेशिता और समान अवसर विज्ञापन इस प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण लाभ समावेशिता है। टियर-3 कस्बों, शहरों और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को समान अवसर मिलेंगे। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को दूर करता है और सभी छात्रों के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अवसर सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष एनईईटी विवाद भारतीय परीक्षा प्रणाली में तकनीकी बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। जेनरेटिव एआई और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियां भविष्य में ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए व्यवहार्य समाधान प्रदान करती हैं। डिजिटलीकृत, लचीली और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली को अपनाकर, हम अधिक विश्वसनीय और तनाव मुक्त परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। एक आधुनिक परीक्षा प्रणाली आशा की किरण है, जो एक ऐसे भविष्य का वादा करती है जहाँ प्रत्येक छात्र को सफल होने का समान अवसर मिले। प्रौद्योगिकी, जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो शिक्षा क्षेत्र को बदलने, अखंडता, समावेशिता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने की शक्ति रखती है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

आर्थिक विकास के आकलन

भारत सरकार के डाटा ने 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में आर्थिक विकास दर 6.7 फीसदी बताई थी, लेकिन विश्व बैंक का आकलन सामने आया है कि इस साल भारत की बढ़ोतरी दर 7 फीसदी रहनी चाहिए। उसके आकलन के अपने आधार हैं। वह मानता है कि निजी उपभोग और मांग में उछाल आएगा। औसत उपभोक्ता खरीददारी करने बाजार तक जाएगा। जाहिर है कि बाजार में भी पैसा आएगा। वही आर्थिक विकास की दर तय करता है। विश्व बैंक ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और एशियन डिवेलपमेंट बैंक आदि वैश्विक एजेंसियों के भी आकलन और अनुमान विश्व बैंक सरीखे हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ोतरी दर को कुछ ज्यादा ही आंका है और उसे 7.2 फीसदी माना है। रिजर्व बैंक ने पहली तिमाही का अनुमान भी 7.1 फीसदी लगाया था, लेकिन बढ़ोतरी 6.7 फीसदी ही दर्ज हो पाई। भारत की अर्थव्यवस्था के ऐसे अंतरराष्ट्रीय आकलन बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी वैश्विक एजेंसियों के आकलन लगभग समान हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और सबसे तेज गति से बढ़ रही है। विश्व बैंक के आकलन का आधार यह है कि निजी खपत की बढ़ोतरी दर पहली तिमाही में 7.4 फीसदी रही है, जबकि पिछले साल यह 4 फीसदी थी। इसका बड़ा कारण है कि ग्रामीण आमदनी में उछाल आया है, लिहाजा प्रति व्यक्ति उपभोग भी बढ़ा है। हालांकि शहर में औसतन निजी खपत कम रही है। बीते साल अल नीनो के बाद एक बेहतर मॉनसून सत्र रहा है और अच्छी बारिश हुई है।

गर्मियों में भीषण लू के बावजूद कृषि उत्पादन बढ़ा है, लिहाजा आय बढ़ी है, तो खपत और मांग भी बढ़ी हैं। विश्व बैंक का आकलन है कि निवेश की बढ़ोतरी में हल्की-सी मंदी आएगी, लिहाजा सरकारी पूंजी व्यय में बढ़ोतरी कुछ धीमी होगी। विश्व बैंक ने आगामी दो वित्त वर्ष 2025-27 के दौरान भी औसत बढ़ोतरी की दर 6.7 फीसदी आंकी है, जो 7 फीसदी के करीब ही है। बल्कि 7 फीसदी अथवा उससे अधिक भी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन है कि अगले कुछ वर्षों के दौरान भारत की आर्थिक बढ़ोतरी दर करीब 6.5 फीसदी रहेगी। रपट में भारत के निर्यात का भी विश्लेषण किया गया है। गौरतलब है कि भारत उस खाली स्थान का फायदा नहीं उठा पा रहा है, जो चीन के कम हुनरमंद विनिर्माण क्षेत्र के सिकुडऩे के कारण रिक्त हुआ था। हालांकि बांग्लादेश और वियतनाम चीन की इस सिकुडऩ के 'प्राथमिक लाभार्थी' रहे हैं। परिधान, चमड़ा, वस्त्र और जूते

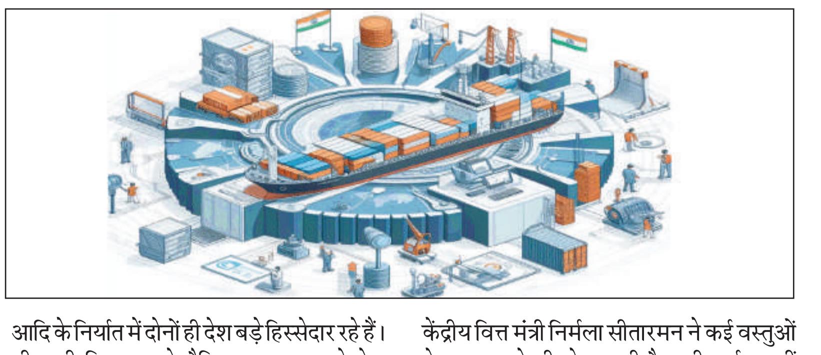

आदि के निर्यात में दोनों ही देश बड़े हिस्सेदार रहे हैं। चीन की सिकुडऩ से वैश्विक स्तर पर जो देश लाभान्वित हुए हैं, उनमें पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस आदि हैं। विश्व व्यापार संगठन की शर्तें भी भारत के लिए बाधा बनती हैं। उनमें वस्तुओं के दाम भी मुख्य समस्या हैं। रोजगार की भी समस्या है। विनिर्माण और सेवाओं के निर्यात गहन कौशल वाले बन गए हैं। अधिक हुनर अपेक्षित है। निर्यात से जुड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार गिरे हैं। इस बार के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई वस्तुओं के दाम घटाने की घोषणा की है। यही पर्याप्त नहीं है। अभी बहुत कुछ करना शेष है, ताकि निर्यात लगातार बढ़ सके।

सरकार को अधिक देशों के साथ 'मुक्त व्यापार समझौते' करने चाहिए और दुनिया की कीमती शृंखला वाले कारोबार के साथ एकीकरण करना चाहिए। बेशक निर्यात वाले मोर्चे पर कई चुनौतियां हैं। उन्हें यथाशीघ्र संबोधित करने की जरूरत है। उनसे हमारी बढ़ोतरी की दर लगातार बढ़ती रहेगी। आर्थिक विकास के नए अनुमान जता रहे हैं कि कोरोना काल की धीमी आर्थिक विकास दर के बाद अब तेजी का रुख आने वाला है। कोरोना काल में आम लोगों की खरीद क्षमता प्रभावित हुई थी जिसके कारण बाजार में मांग उत्पन्न नहीं हुई। इसके कारण हमारा व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब देखा यह जा रहा है कि आम लोगों की खरीद क्षमता में बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण बाजार में मांग पैदा हुई है। अनुमान है कि अब व्यापार अच्छा चल निकलेगा। इसी के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास दर बढऩे का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत को अपने निर्यात क्षेत्र पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यदि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो, तो यह लाभ का सौदा माना जाता है। जिन देशों के लिए भारत से निर्यात की संभावनाएं हैं, उन देशों के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी जरूरत है।

राय

सदन में मीडिया

सदन के भीतर मीडिया खुद को अंगीकार कर सकता है, बशर्ते उसके भीतर अपने प्रोफेशन की नैतिकता का सदन हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम विधायक रणधीर शर्मा के रास्ते पर हिमाचल का मीडिया उस समय खड़ा मिला, जब पत्रकारिता की वास्तविकता में उसकी निष्पक्षता पर अंगुली उठी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा में आए ठहराव की वजह पूछी गई। यहां मीडिया पर बहस के सिर्फ दो पक्ष देखे गए, जबकि अनेक बिंदुओं पर हिमाचल के मीडिया पर एक व्यापक चर्चा की जरूरत है, क्योंकि मीडिया न तो प्रेस नोट हो सकता है और न ही प्रेस कांफ्रेंस की चाय में चुस्की भर हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री अगर मीडिया के सवाल को बड़ा कर रहे हैं, तो उसका उत्तर हिमाचल की पत्रकारिता को भी देना होगा। यहां मीडिया के भ्रम में मीडिया कर्मियों का सैलाब खड़ा है, कलम की जगह मोबाइल से पाला पड़ा है। जरा गौर करें कि प्रेस कांफ्रेंस की अग्रिम पंक्ति में क्या अब पत्रकारिता की वरिष्ठता दर्ज होती है। बेशक पिछले तीन दशकों से हिमाचल की पत्रकारिता में प्रोफेशनल प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, लेकिन यह करियर की उड़ान से पहले पत्रकारों के चरित्र में हार गई। पत्रकारिता ने कई द्वार चुन लिए, प्रवेश के लिए डिजिटल मीडिया ने कारोबार चुन लिया, जहां मीडिया के संबोधन न मिशन, न मुराद और न ही मकसद लेकर चल रहे हैं। पारंपरिक मीडिया के अपने दबाव भी हैं। खास तौर पर जो प्रकाशन हिमाचल की धरती पर पत्रकारिता का आसमान लेकर आए हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार के करीब रोजगार दिया है। अखबार अपने आप में एक आर्थिकी का संचार भी है और यह सत्य प्रदेश में स्थापित आधा दर्जन से ऊपर प्रिंटिंग प्रेस साबित कर रहे हैं। पत्रकारिता का मूल्यांकन होना चाहिए और हर दिन पाठक, दर्शक व श्रोता यही विश्लेषण निरंतर करते रहते हैं। पूरे प्रदेश के अखबार विक्रेता बता सकते हैं कि पाठकों की रुचि किस तरह की लिखावट में है, लेकिन प्रदेश में बिना टांग के भी पत्रकारिता के खत दौड़ रहे हैं। अगर पत्रकारिता सियासत की चुगलखोर बन जाए, तो फिर मूल्यांकन होगा कैसे। दरअसल हिमाचल में मीडिया के माध्यम से विश£षण, तथ्यपूर्ण अन्वेषण और आलोचनात्मक पत्रकारिता का दबाव में दहन होने लगा है। इस दौरान पत्रकारिता का पैगाम अगर बदलते-बदलते विधानसभा सदन की चिंता में परिलक्षित हो रहा है, तो आत्म विश£षण की राह पर मीडिया को गंगा में स्नान करना पड़ेगा। दूसरी ओर प्रिंट मीडिया के सामने 'मोबाइल मीडिया' को जवाबदेह बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ पत्रकारों को कुछ फासले और कुछ आचार संहिता का निर्वहन कराने के लिए सामने आना होगा। विडंबना यह है कि नेताओं को भी मालूम नहीं कि उनके वीडियो में प्रदर्शित सोशल मीडिया का उबाल घातक है और इस तरह घात-प्रतिघात के लिए 'कुछ मेरे-कुछ तेरे' पत्रकारों का चयन मीडिया की भाषा और सरोकारों को निचले स्तर तक पहुंचा रहा है। जो मुख्यमंत्री ने कहा वह एक हद तक हकीकत है और जो रणधीर शर्मा ने कहा वह पत्रकारिता की आत्मा से निकली संवेदना है। ऐसे में मीडिया को सशक्त, निष्पक्ष और प्रोफेशनल बनाने के लिए राजनीति को भी कुछ सबक और कुछ तथ्यात्मक आलोचना के घूंट पीने के लिए हिम्मत दिखानी होगी। वैसे हिमाचल विधानसभा अगर पिछले दिनों मीडिया जगत से दिवंगत हुए गौरव बिष्ट व आनंद बौद्ध को श्रद्धांजलि दे, तो मीडिया में प्रतिष्ठित होने की परंपरा को आत्मबल मिलेगा।

पैरा ओलंपिक में निषाद को फिर रजत

टोक्यो ओलंपिक में निषाद ने भारत के लिए टी-47 स्पर्धा में रजत पदक जीत कर हिमाचल से पहला पैरा ओलंपिक पदक विजेता बन गया। डीएवी चंडीगढ़ व जालंधर की लवली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करने वाले इस हाई जंपर ने 2023 पेरिस व 2024 कोवे में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीते हैं। 2022 एशिया पैरा खेल, जो चीन के शहर हांगजों में हुए थे, उसमें भी टी-47 स्पर्धा में 2.06 मीटर ऊंचा कूद कर देश के लिए रजत पदक जीता है। निषाद कुमार का एथलेटिक्स सफर हर किसी के लिए प्रेरणास्रोत है'

ओलंपिक खेलों में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात है। तब तो पदक जीतने वाला खिलाड़ी विशेष ही होता है। भारत में जहां अभी खेल सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है, वहां पर खिलाड़ी को अपने खेल जीवन के शुरुआती दौर में विभिन्न कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बात जब खेलों में बहुत पिछड़े राज्य हिमाचल से हो और ऐसे में कोई विश्व स्तर पर जाकर ओलंपिक में पदक जीतता है, तो उस महामानव को सलाम करना बनता ही है। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। चार वर्षों बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ का नजारा ही अलग होता है। अब समर ओलंपिक खत्म होने के बाद पैरा एथलीटों के लिए भी ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं। आजकल पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के उपमंडल अंब के बडुआं गांव के निषाद कुमार ने ऊंची कूद की टी-47 स्पर्धा में देश के लिए ओलंपिक में दूसरी बार 2.04 मीटर ऊंची कुदान लगा कर रजत पदक जीता है। इससे पहले इसी स्पर्धा में निषाद टोक्यो ओलंपिक 2021 में देश के लिए रजत पदक जीत चुका है। 3 अक्टूबर 1999 को पिता रछपाल सिंह व माता पुष्पा देवी के घर जन्मे निषाद कुमार का छह वर्ष की आयु में घास काटने की मशीन से उसका दायां बाजू कट जाने के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे भविष्य में यह बालक दो ओलंपिक में लगातार पदक जीतेगा।

माता पुष्पा देवी, जो अपने समय की वॉलीबाल खिलाड़ी व चक्का प्रक्षेपक रही थी, उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे का भविष्य खेल में तलाशा। निषाद ने गांव के विद्यालय में पढ़ते समय ही ऊंची कूद में लंबी उड़ान की सोच ली थी। पूरे हिमाचल का अपनी स्पर्धा में चैंपियन बनने के बाद जब देखा हिमाचल में ऊंची कूद के लिए न तो आधारभूत सुविधा थी और न ही प्रशिक्षक। ऐसे में प्रदेश से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। पहाड़ की संतानों को अभी तक न तो सही परिचय ही मिलता है और न ही प्रश्रय। पलायन में शहर दर शहर भटकना पड़ता है। पहले पंचकूला और फिर किसी की सलाह पर बंगलौर का रुख किया और वहां पैरा एथलेटिक्स महासंघ के सचिव सत्यनारायण की देखरेख में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया और फिर ओलंपिक के पदक को चूमा। निषाद ने 2013 में पटियाला में आयोजित स्कूल नेशनल में रजत पदक जीत कर भविष्य के विजेता होने का संकेत तो दे दिया, मगर पैरा नेशनल में पदक के लिए 2017 पंचकूला आयोजन का इंतजार करना पड़ा। इस नेशनल में निषाद ने 1.83 मीटर कूद कर पहला रजत पदक जीता था। 2019 दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद की टी-47 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। 2021 दुबई में हुई विश्व पैरा ग्रांप्री में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में निषाद ने भारत के लिए टी-47 स्पर्धा में रजत पदक जीत कर हिमाचल से पहला पैरा ओलंपिक पदक विजेता बन गया। डीएवी चंडीगढ़ व जालंधर की लवली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करने वाले इस हाई जंपर ने 2023 पेरिस व 2024 कोवे में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीते हैं। 2022 एशिया पैरा खेल, जो चीन के शहर हांगजों में हुए थे, उसमें भी टी-47 स्पर्धा में 2.06 मीटर ऊंचा कूद कर देश के लिए रजत पदक जीता है।

निषाद कुमार का एथलेटिक्स सफर हर किसी के लिए प्रेरणास्रोत है। जहां अभी तक अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य पढ़ाई में देखते हैं, निषाद के माता-पिता ने उसका भविष्य खेल, वह भी ऊंची कूद में देखा, जिस स्पर्धा में हिमाचल प्रदेश का कोई इतिहास ही नहीं था। यह अलग बात है कि निषाद ने तो अब स्वर्णिम इतिहास रच दिया है जिस पर हिमाचल ही नहीं, अपितु पूरा देश गर्व कर सकता है। हिमाचल सरकार को भी चाहिए कि

वह निषाद कुमार को सम्मानजनक नौकरी व घोषित नगद ईनाम जल्द से जल्द देकर खिलाड़ी का सम्मान करे। जहां तक देश में खेल ढांचे का प्रश्न है, भारत को अभी खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटानी हैं। हिमाचल में आधारभूत खेल ढांचा तो उपलब्ध है, पर उसके विस्तार की जरूरत है। खेल ढांचे के लिहाज से हरियाणा को हिमाचल से काफी आगे समझा जाता है। अगर हिमाचल में भी हरियाणा की तरह की खेल सुविधाएं खिलाडियों को मिल जाएं, तो यहां की प्रतिभाएं भी कमाल दिखा सकती हैं। हिमाचल में प्रदेश सरकार को पर्याप्त संख्या में खेल प्रशिक्षक भी नियुक्त करने हैं। उच्च कोटि के खिलाड़ी बिना प्रशिक्षकों के ईजाद नहीं किए जा सकते। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह पूर्व खिलाडियों को अनुबंध के आधार पर पांच-पांच साल के लिए नियुक्त करे। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो इस अनुबंध को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जरूरत इस बात की भी है कि हिमाचल में जो खेल मैदान उपलब्ध हैं, उनका ठीक ढंग से रखरखाव हो और ऐसे मैदानों का प्रयोग मात्र खेल गतिविधियों के लिए ही हो। हिमाचल में कुछ खेल मैदानों का प्रयोग फिलहाल सैर-सपाटे के लिए भी किया जा रहा है, ऐसी गतिविधियां बंद की जानी चाहिए और उपलब्ध खेल ढांचे का पर्याप्त रखरखाव तथा सदुपयोग होना चाहिए। जो खेल प्रशिक्षक अपने स्तर पर प्रशिक्षण गतिविधियां चला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रदेश सरकार को कुछ करना चाहिए। पदक जीतने वाले खिलाडियों को पुरस्कार और सरकारी नौकरी का आबंटन भी जल्द हो।

ईमेल:
bhupindersinghhmr@gmail.com
भूपिंद्र सिंह

कुकी विवाद पर शेख हसीना का रहस्योद्घाटन

अमेरिका चीन और भारत दोनों पर नजर रखना चाहता है। चीन भी आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर देने की दिशा में बढऩे का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत का मामला उससे भी पेचीदा है। यह ठीक है कि अमेरिका और भारत की किसी स्तर पर भी समानता नहीं है, लेकिन आज अमेरिका समेत पूरे यूरोप में जो 'सभ्यताओं का संघर्ष' चला हुआ है उसमें भविष्य में भारत का पलड़ा भारी हो सकता है। इसलिए अमेरिका को राजनीतिक रूप से अस्थिर भारत अनुकूल लगता है। पिछले एक दशक से भारत की राजनीतिक स्थिरता और बहुमत की सरकार सामी सभ्यताओं वाले अमेरिका की आंख की किरकिरी थी। उसे बीसियों विचारधाराओं के दलों की खिचड़ी सरकारें अनुकूल लगती हैं'

मणिपुर में मैतेयी और कुकी समुदाय का विवाद काफी लम्बा खिंचता जा रहा है। कुकी विद्रोहियों के हाथ में लूटपाट से भारी मात्रा में हथियार जमा हो गए हैं जिसके कारण हिंसा थम नहीं रही है। अभी तक इस विवाद को स्थानीय विवाद समझ कर विपक्ष हल्ला गुल्ला करता रहता है। लेकिन पिछले दिनों बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ स्पष्ट बातें कही थीं जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही थी। उनका कहना था कि अमेरिका ने बांग्लादेश में कुछ देश विरोधी ताकतों को उनके पद से हटाया है। लेकिन उनके अनुसार अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन नामक टापू लीज पर मांग रहा था और वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थीं। इसलिए अमेरिका ने सारी साजिश रची। शेख हसीना के इस रहस्योद्घाटन की देश-विदेश में खूब चर्चा हुई। लेकिन इसके साथ पूर्व प्रधानमंत्री ने एक दूसरा रहस्योद्घाटन भी किया। उसके अनुसार अमेरिका चिटगांव, भारत के कुकी बहुल इलाकों और म्यांमार के कुकी बहुल काचिन प्रदेश को मिला कर पूर्वोत्तर भारत में एक ईसाई देश का गठन करने का प्रयास कर रहा है। आश्चर्य है कि विदेशी मीडिया ने शेख हसीना के इस पर्दाफाश की अवहेलना की, लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि भारत का मीडिया भी इस विषय पर एकदम से खामोशी का शिकार हो गया। पूर्वोत्तर भारत के कुकी बहुल इलाके कौनसे हैं? उनमें सबसे पहले तो मणिपुर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है जहां कुकी समुदाय का बाहुल्य है। मणिपुर का पड़ोसी प्रदेश मिजोरम है।

मिजोरम के निवासी 'जो' भी कुकी समाज का हिस्सा ही माने जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मिजोरम और मणिपुर में मैतेयी बहुल इम्फाल घाटी को छोडक़र शेष सारा मणिपुर कुकी समुदाय का इलाका माना जाता है। मिजोरम और मणिपुर के पड़ोस में म्यांमार लगता है। म्यांमार का काचिन प्रदेश कुकी बहुल प्रदेश है। इस काचिन प्रदेश को म्यांमार से अलग करने के लिए विद्रोही समय समय पर आघात करते रहते हैं। मणिपुर में कुकी विद्रोह से पहले म्यांमार का काचिन प्रदेश विद्रोहियों के कब्जे में आ गया था। उसके बाद ही मणिपुर में गड़बड़ शुरू हुई। दरअसल म्यांमार में पहाड़ी क्षेत्र में पिछले कई सालों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के शासन काल में ही विदेशी ईसाई मिशनरियां सक्रिय हो गई थीं। अब तक उन्होंने पूरे पहाड़ी क्षेत्र की जनजातियों को मतांतरित करके ईसाई बना लिया है। इन मतान्तरित क्षेत्रों में चिन/कुकी बहुल चिन प्रदेश भी शामिल हैं। वहां से कुकी निरन्तर मणिपुर में आते जाते रहते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सत्ता गंवाने से ठीक पहले कुकी बहुल क्षेत्र की पहचान को पुख्ता व स्पष्ट स्थापित करने के लिए पूरे मणिपुर का नक्शा ही बदल दिया था। उसने अनेक जिलों को इस प्रकार विभाजित किया ताकि कुकी बहुल जिलों का निर्माण किया जा सके। इसी प्रकार बंग्लादेश के चिटगांव से कुकी विद्रोही आघात प्रत्याघात करते रहते हैं। इसमें एक दूसरा तथ्य भी ध्यान में रखना होगा। मिजोरम, मणिपुर, चिटागांव और म्यांमार के चिन प्रदेश के कुकी शत-प्रतिशत अपनी विरासत छोडक़र ईसाई मत में जा चुके हैं। मणिपुर-मिजोरम-चिटगांव-चिन क्षेत्र के कुकी समाज को कुकी-जो-चिन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अंग्रेज भारत से जाने के पहले 1947 में ही भारत को घेरने की योजना पर काम कर रहे थे।

पूर्वोत्तर भारत में एक ईसाई देश बनाने की योजना थी जिसे कूपलैंड योजना कहा जाता था और पश्चिमोत्तर भारत में एक मुसलमान देश बनाने की योजना थी जिसे जिन्ना योजना कहा जाता था। जिन्ना योजना तो पश्चिमोत्तर भारत की राजनीति का हिस्सा बन गई, लेकिन कूपलैंड योजना में अभी ब्रिटिश साम्राज्यवादी रंग भर ही रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त हो गया और अंग्रेजों को इस योजना को अधूरी छोड़ कर जाना पड़ा। असम के उस समय के राज्यपाल राबर्ट नायल राईड्स ने 1941 में ही शिलांग की एक गोपनीय बैठक में इस योजना का ख़ुलासा करते हुए कहा था कि 'बर्मा के काचिन क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तरीय पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके ऐसा नया देश बनाने की योजना है जिस पर इंग्लैंड का शासन हो।' अंग्रेज जानते थे कि जिन्ना योजना से पैदा होने वाले देश पाकिस्तान पर वे प्रत्यक्ष शासन नहीं कर पाएंगे। वहां तो रणनीतिक सांझेदारी ही हो सकती है। लेकिन बर्मा और भारत के एक हिस्से को काट कर बनाए गए नए ईसाई देश को वे अपना उपनिवेश बना सकेंगे। लेकिन भारत की पूर्वोत्तर सरहद पर नया देश बनाने की इच्छा पूरी होने से पहले ही अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा। अब इस पृष्ठभूमि में शेख हसीना का रहस्योद्घाटन चौंकाता कम चिन्तित ज्यादा करता है। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करना होगा कि लगभग एक दशक पहले कांग्रेस सरकार ने मणिपुर में कुकी क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए नए जिले क्या कुकी क्षेत्रों को मणिपुर से अलग करने के लिए ही गठित किए थे? इसमें तो कोई शक नहीं कि बर्मा के काचिन क्षेत्र में कुकी समुदाय के लोगों को ईसाई बनाने के काम में लगी मिशनरियों को अमेरिका से धन ही नहीं, अन्य प्रकार की सहायता भी मिल रही है। लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि अमेरिका को इस नए ईसाई देश से क्या फायदा होगा? जिस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में बदलाव होता रहता है, उसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देशों के स्वार्थ और रिश्ते बदलते रहते हैं।

जिस कॉलेज ने नहीं दिया दाखिला, उसी ने लेक्चर के लिए भेजा निमंत्रण; अदाणी ने सुनाए कामयाबी के किस्से

परिवहन विशेष न्यूज

दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अदाणी का नाम भी शामिल है। गौतम अदाणी ने 16 साल के बाद पढ़ाई को छोड़कर बिजनेस में हाथ आजमाया । टीचर्स डे के मौके पर गौतम अदाणी ने मुंबई के कॉलेज में लेक्चर दिया। यह वही कॉलेज है जिस कॉलेज ने अदाणी के एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया था।

नई दिल्ली। देश के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अदाणी का नाम भी शामिल है। जब भी दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट आती है तो भारतीय अरबपतियों का भी जिक्र किया जाता है। गौतम अदाणी ने कामयाबी की बुलंदियों को हासिल करने में कई चुनौतियों का सामना किया है। गौतम अदाणी ने शिक्षक दिवस के मौके पर इन चुनौतियों का जिक्र किया।

अदाणी ने किन चुनौतियों का सामना किया है, यह बताने से पहले उन्होंने कॉलेज का एक किस्सा बताया। दरअसल, गौतम अदाणी जिस कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, उसी कॉलेज ने उन्हें एडमिशन नहीं दिया था।

कॉलेज ने नहीं दिया था एडमिशन

गौतम अदाणी ने अपनी कामयाबी से जुड़े कई किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि 1970 में वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई आए थे। मुंबई के कॉलेज में उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया। कॉलेज में एडमिशन न मिलने की वजह से उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की और वह वापस अपने शहर लौट गए।

आज उसी कॉलेज ने उन्हें वापस बुलाया। जी हां, इस कॉलेज का नाम जय हिंद है। कॉलेज के एडमिशन को लेकर पूर्व छात्रों के संघ के चेयरमैन विक्रम नानकानी ने बताया गौतम अदाणी 16 साल की उम्र में एडमिशन के लिए आए है। गौतम अदाणी ने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन दिया था। नानकानी ने बताया कि गौतम अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी (Vinod Adani) भी इसी कॉलेज में पढ़े थे।

'ब्रेकिंग बाउंड्रीज़: द पावर ऑफ पैशन एंड अनकन्वेंशनल पाथ्स टू सक्सेस' पर गौतम अदाणी ने कहा कि उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार सीमा तोड़ने का फैसला लिया था। गौतम अदाणी ने खुद बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई-लिखाई छोड़कर बिजनेस शुरू किया था।

गौतम अदाणी बताते हैं कि कई लोग मेरी पढ़ाई छोड़ने और मुंबई जाने की वजह पूछते हैं। इस सवाल का जवाब है कि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुंबई एक तरह से मेरा ट्रेनिंग प्लेस था। यहां मैंने सीखा है कि बिजनेस कैसे करते हैं। इसके अलावा इस मायानगरी ने मुझे बड़ा सोचना भी सिखाया है।

एडमिशन न मिलने पर छोड़ दी पढ़ाई

गौतम अदाणी को जब कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने मुंबई में दो साल तक हीरा छांटने का काम किया। 2 साल यह काम करने के बाद वह गुजरात वापस चले गए। गुजरात जाने के बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और कामयाबी हासिल की। आज बिजनेस सेक्टर में सफल कंपनियों में अदाणी ग्रुप (Adani Group) का नाम शामिल है।

कैसे शुरू हुआ अदाणी ग्रुप

गौतम अदाणी ने 1998 में अदाणी ग्रुप की शुरुआत की है। गौतम अदाणी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने जिंसों में व्यापार शुरू किया। जिंसो में व्यापार शुरू करने के बाद उन्होंने ढाई साल के बाद बंदरगाह, खदान, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सिटी गैस, रिन्यूवेबल एनर्जी, सीमेंट और डेटा सेंटर आदि सेक्टर में कदम रखा।

लगातार दूसरे दिन मालामाल हुए निवेशक, 18 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया स्टॉक

शेयर बाजार में रामा स्टील के शेयर शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। शेयर में आई शानदार तेजी के बाद शेयरहोल्डर्स को काफी फायदा हुआ है। शुरुआती कारोबार में ही रामा स्टील के शेयर 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। आइए जानते हैं कि कंपनी के शेयर में तेजी क्यों आई।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में बिकवाली भरे कारोबार के बीच रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर में शानदार तेजी आई है। बता दें कि रामा स्टील के शेयर पेन्नी स्टॉक है। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। खबर लिखते वक्त रामा स्टील के शेयर 18.24 फीसदी या 2.53 रुपये चढ़कर 16.40 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

शेयर में क्यों आ रही है तेजी

रामा स्टील के शेयरों में तेजी आने के पीछे मुख्य तीन कारण हैं।

एक्सचेंज फाइलिंग की जानकारी के अनुसार अमेरिका के मिनर्वा वेंचर्स फंड ने कंपनी में निवेश किया है। मिनर्वा वेंचर्स फंड में करोड़ों शेयर खरीदे हैं। वहीं, ईबिसु ग्लोबल ऑप्र्च्यूनिटीज ने भी 3 करोड़ स्टॉक खरीदे हैं।

राम स्टील ने पिछले 8 सालों में 3 बार बोनस शेयर दिया है। 2016 में 4:1, मार्च 2024 में 2:1 के बोनस शेयर दिये थे। अब कंपनी ने 1:2 रेश्यो के बोनस शेयर देने का एलान किया है।

रामा स्टील की सहायक कंपनी रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड अब डिफेंस सेक्टर में उतरने के लिए तैयार है। इस यूनिट को कंपनी के बोर्ड से मंजूरी मिल गई है।

रामा स्टील शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 25.19 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं मार्च 2024 से लेकर सितंबर तक में कंपनी के शेयर में 22.21 फीसदी की तेजी आई। पिछले तीन कारोबारी सत्र में ही कंपनी ने निवेशकों को शेयर के जरिये 57 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे दिया।

शेयर मार्केट में हाहाकार, निवेशकों के 4.12 लाख करोड़ स्वाहा; किस बात से सहमा बाजार?

दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अमेरिका काफी वक्त से मंदी की आशंका से जूझ रही है। गुरुवार को भी वहां जॉब से जुड़े डेटा काफी कमजोर आए। साथ ही यूएस नॉन-फर्म पेरोल्स डेटा को लेकर भी अमेरिकी निवेशक काफी सतर्क हैं। इससे ओवरऑल सेंटिमेंट काफी कमजोर है। इसके चलते अमेरिका और दुनियाभर के अन्य बड़े शेयर बाजारों में गिरावट आई है जिसका असर भारत पर भी दिख रहा है।

नईदिल्ली। भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी 1 फीसदी तक गिर गए थे। इससे निवेशकों की करीब 4.12 लाख करोड़ की पूंजी स्वाहा हो गई। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से SBI, HCL टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदाणी पोर्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज्यादा गिरावट दिखी। वहीं, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर हरे निशान में थे।

शेयर मार्केट में गिरावट की वजह

दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अमेरिका काफी वक्त से मंदी की आशंका से जूझ रही है। गुरुवार को भी वहां जॉब से जुड़े डेटा काफी कमजोर आए। साथ ही, यूएस नॉन-फर्म पेरोल्स डेटा को लेकर भी अमेरिकी निवेशक काफी सतर्क हैं। इससे ओवरऑल सेंटिमेंट काफी कमजोर है। अमेरिकी शेयर मार्केट में पिछले कुछ सत्रों से गिरावट देखी जा रही है। इन फैक्टर का असर दुनियाभर के बाजारों पर पड़ा और उनमें भी गिरावट आई। इनमें भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग जैसे एशियाई बाजार भी शामिल हैं।

मुनाफावसूली भी है एक कारण

बैंकों की घटती डिपॉजिट ग्रोथ भी भारतीय निवेशकों की चिंता बढ़ने की बड़ी वजह है। इससे फाइनेंस सेक्टर के हैवीवेट शेयरों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया डेटा से पता चलता है कि जून तिमाही में डिपॉजिट ग्रोथ 11.7 फीसदी रही, वहीं लोन ग्रोथ 15 फीसदी रही। इससे निवेशकों को डर है कि बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा प्रभावित हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैंकों की घटती ग्रोथ पर चिंता जता चुकी हैं।

महंगाई से राहत: सस्ती हुई शाकाहारी थाली, सावन का पवित्र महीना बना वजह

परिवहन विशेष न्यूज

महंगाई की मार के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अगस्त में घर में पकाए जाने वाले भोजन की लागत में कमी आई है। इनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन शामिल हैं। इन दोनों थालियों की लागत घटने में सावन के पवित्र महीने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस दौरान कई जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

नई दिल्ली। टमाटर और पोल्ट्री की कीमतों में गिरावट से अगस्त के दौरान घर में पकाए जाने वाले भोजन की लागत में कमी आई है। इसकी वजह सावन का पवित्र महीना रहा, जिसमें बहुत से परिवार नॉन-वेज नहीं खाते। यह जानकारी घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट से मिली है। इसके मुताबिक, शाकाहारी भोजन की कीमत जुलाई के 32.6 रुपये प्रति प्लेट से 4 प्रतिशत घटकर अगस्त में 31.2 रुपये रह गई। पिछले साल अगस्त में यह 34 रुपये थी।

नॉन-वेज थाली का दाम भी घटा

क्रिसिल की 'रोटी राइस रेट' रिपोर्ट बताती है कि मांसाहारी थाली की कीमत पिछले महीने की तुलना में 3 प्रतिशत घटकर 59.3 रुपये रह गई। हालांकि, एक साल पहले के मुकाबले यह 12 फीसदी महंगी हुई है। इस मासिक रिपोर्ट के अनुसार, टमाटर की कीमतें घटकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गईं। यह मासिक आधार पर 23 फीसदी और सालाना आधार 51 फीसदी की गिरावट है। इसी वजह से खाने का दाम भी कम हो गया।

अगस्त में ब्रॉयलर भी सस्ता हुआ

शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जियां (प्याज, टमाटर और आलू), चावल, दाल, दही और सलाद शामिल हैं। वहीं, मांसाहारी थाली में दाल की कीमतों की जगह ब्रॉयलर (Broiler) का दाम शामिल हैं। ब्रॉयलर मांस के लिए पाले जाने वाले चिकन को कहते हैं। सावन महीने में जुलाई की तुलना में ब्रॉयलर की कीमतों में 3 प्रतिशत और सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके कारण पिछले साल की तुलना में भोजन की कीमतों में तेज गिरावट आई।

और भी सस्ती हो सकती थी थाली

इस साल की शुरुआत में एलपीजी की कीमतों में कमी के कारण ईंधन की लागत में 27 प्रतिशत की कमी आई। साथ ही, वनस्पति तेल, मिर्च और जीरे की कीमतों में गिरावट ने भी पिछले साल की तुलना में भोजन की लागत को कम करने में मदद की। भोजन और सस्ता हो सकता था, लेकिन प्याज की कीमतों में 15 रुपये और आलू की कीमतों में 13 रुपये प्रति किलो की सालाना आधार पर वृद्धि ने मामला खराब कर दिया।

टाटा के बाद अदाणी ग्रुप भी लगाएगा सेमीकंडक्टर प्लांट, इजरायल की मिलेगी मदद

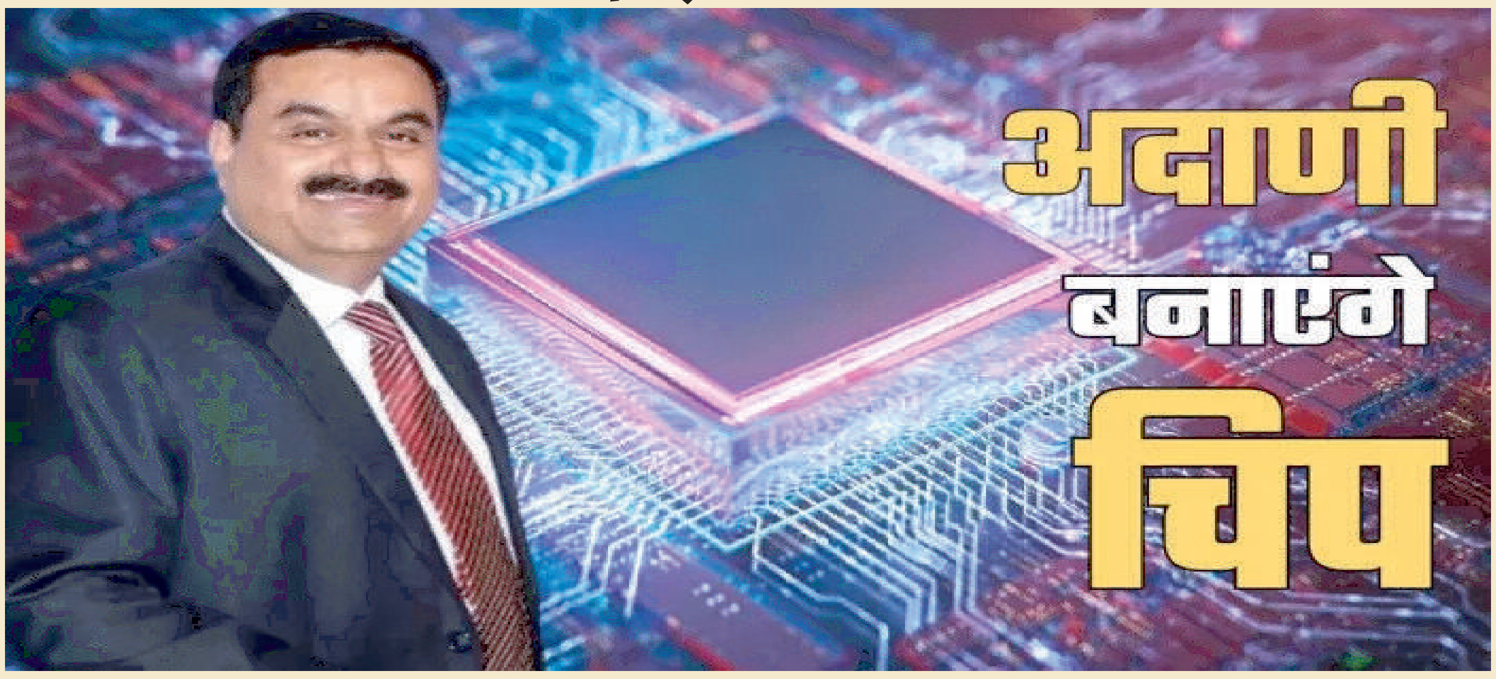

भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के लिए जोरशोर से कदम उठा रहा है। टाटा ग्रुप दो सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। अब अरबपति कारोबारी कारोबारी गौतम अदाणी का अदाणी ग्रुप भी सेमीकंडक्टर बनाने की दौड़ में शामिल हो गया है। टाटा के बाद अदाणी ग्रुप भी लगाएगा अदाणी समूह अभी तक बंदरगाह ट्रांसमिशन सीमेंट और कोयला कारोबार में हैं और चिप निर्माण समूह के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा।

नईदिल्ली। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी का अदाणी समूह और इजरायल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में 10 अरब डॉलर (83 हजार करोड़ रुपये) की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी। भारत ने वैश्विक चिप कंपनियों को देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को दुनिया का चिपमेकर हब बनाने का लक्ष्य रखा है।

सेमीकंडक्टर की राह मुश्किल

ताइवान की फॉक्सकॉन ने पिछले साल जुलाई में भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ 19.5 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर ज्वाइंट वेंचर से हाथ खींच लिया था। इतना ही नहीं अबुधाबी स्थित नेक्स्ट आर्बिट वेंचर्स और टावर सेमीकंडक्टर भारत में तीन अरब डॉलर की लागत से एक उद्यम लगाने का एलान किया था, लेकिन बाद में यह योजना भी ठप हो गई। हालांकि शुरुआती असफलताओं के बावजूद भारत को उम्मीद है कि 2026 तक उसका सेमीकंडक्टर बाजार 63 अरब डॉलर का हो जाएगा।

अदाणी समूह अभी तक बंदरगाह, ट्रांसमिशन, सीमेंट और कोयला कारोबार में हैं और चिप निर्माण के क्षेत्र में कदम रखना उनके समूह के लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस संयंत्र में शुरुआत में 40 हजार वेफर्स बनाए जाएंगे।

विदेशी निवेश में महाराष्ट्र अव्वल

चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, महाराष्ट्र को अप्रैल से जून के दौरान 70,795 करोड़ रुपये का एफडीआई मिला है।

कर्नाटक 19,059 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आकर्षित करके दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली 10,788 करोड़ रुपये के साथ तीसरे, तेलंगाना 9,023 करोड़ रुपये के साथ चौथे, गुजरात 8,508 करोड़ रुपये के साथ पांचवें, तमिलनाडु 5,818 करोड़ रुपये के साथ छठे, उत्तर प्रदेश 370 करोड़ रुपये के साथ आठवें और राजस्थान 311 करोड़ रुपये के साथ नौवें स्थान पर है।

स्टील डंप के लिए चीन की कसी जाएगी लगाम? वाणिज्य मंत्री कर रहे तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

चीन स्टील बाजार का सबसे दिग्गज खिलाड़ी है। लेकिन वहां 2020 से डिमांड कमजोर है। चीन में प्रॉपर्टी संकट बढ़ने से चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई। इससे स्टील का भाव कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में अपने स्टील को सस्ते भाव में भारत जैसे देशों में डंप करने लगा। चीन में स्टील की डिमांड लंबे वक्त तक कमजोर बनी रहने वाली हैं।

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने इस्पात उद्योग को 'अनुचित' प्रतिस्पर्धा के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उचित कदम उठाए जा सकें। स्टील इंडस्ट्री की कुछ कंपनियों ने चीन से कम कीमत के आयात पर चिंता जताई है।

गोयल ने कहा, 'मैंने इस्पात उद्योग को आमंत्रित किया है कि वे उस अनुचित प्रतिस्पर्धा को समझें जिसका उनमें से कुछ को सामना करना पड़ रहा है, तथा उचित कदम उठाएं ताकि इस्पात उद्योग जीवंत बना रहे, बढ़ता रहे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार जोड़े।' उन्होंने बढ़ते आयात के खिलाफ समान अवसर प्रदान करके घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए सीमा समायोजन कर लागू करने का विचार पांच सितंबर को पेश किया था।

गोयल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जार्डन, इजरायल और यूरोपीय संघ (ईयू) के माध्यम से भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ना है। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह महत्वपूर्ण पहल भारत के समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाएगी और एक रणनीति के रूप में यह बहुत कम मार्गों पर हमारी निर्भरता को कम करेगी जो आज हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकते हैं और इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में भी मदद मिलेगी।"

स्टील डंप क्यों कर रहा चीन

चीन स्टील बाजार का सबसे दिग्गज खिलाड़ी है। लेकिन, वहां 2020 से डिमांड कमजोर है। चीन में प्रॉपर्टी संकट बढ़ने से चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई। इससे स्टील का भाव कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में अपने स्टील को सस्ते भाव में भारत जैसे देशों में डंप करने लगा। चीन की बड़ी स्टील कंपनियों का मानना है कि वहां स्टील की डिमांड लंबे वक्त तक कमजोर बनी रहने वाली हैं। भारत के स्टील निर्माता लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चीन की स्टील डंपिंग पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग बर्बाद हो रहा है।

सिलक्यारा टनल हादसे के बाद अलर्ट मोड पर सड़क परिवहन मंत्रालय, विशेषज्ञ पैनल की मंजूरी के बाद बनेगी 1.5 किमी से लंबी सुरंग

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे से सबक लेते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टनल निर्माण की परियोजनाओं को लेकर सतर्क हो गया है। विशेषज्ञ पैनल गठित कर राज्यों और एनएचएआइ तथा एनएचआइडीसीएल जैसी अपनी एजेंसियों से कहा गया है कि डेढ़ किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली टनल निर्माण परियोजनाओं का प्रस्ताव पैनल को भेजना होगा।राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस का पालन भी सुनिश्चित कराए जाने की जरूरत है।

नई दिल्ली: उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे से सबक लेते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टनल निर्माण की परियोजनाओं को लेकर सतर्क हो गया है। विशेषज्ञ पैनल गठित कर राज्यों और एनएचएआइ तथा एनएचआइडीसीएल जैसी अपनी एजेंसियों से कहा गया है कि डेढ़ किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली टनल निर्माण परियोजनाओं का प्रस्ताव पैनल को भेजना होगा।

विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न मानकों और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर जो सलाह या दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, उसी आधार पर टनल का निर्माण किया जा सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इस आशय की चिट्ठी जारी की गई। इसमें कहा गया है कि टनल निर्माण के दौरान होने वाले हादसे, खास कर सिलक्यारा हादसे को ध्यान में रखते हुए ऐसी परियोजनाओं के डिजाइन और निर्माण की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस का पालन

डीपीआर बनाते समय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस का पालन भी सुनिश्चित कराए जाने की जरूरत है। इसे देखते हुए सरकार ने व्यवस्था की है कि डीपीआर बनाते समय ही टनल परियोजनाओं के जियोलाजिकल, जियो-टेक्निकल, जियो-फिजीकल इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन, सेफ्टी आडिट और निगरानी प्रक्रिया का परीक्षण कर लिया जाए। इसके लिए अकादमिक संस्थानों और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर फ्रेमवर्क तैयार किया है।

सरकार ने विशेषज्ञों का एडवाइजरी पैनल भी गठित किया है, जो डेढ़ किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली टनल परियोजनाओं के निर्माण के लिए तकनीकी व अन्य सलाह देगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रस्तावित ऐसी टनल परियोजनाओं का प्रस्ताव तकनीकी समीक्षा के लिए एडवाइजरी पैनल को भेजना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तरकाशी में नवंबर, 2023 में सिलक्यारा टनल निर्माण के दौरान भूस्खलन की वजह से 41 मजदूर उसमें फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए 17 दिन तक रेस्क्यू आपरेशन चलाना पड़ा। अपने आदेश में मंत्रालय ने उस हादसे का उल्लेख खास तौर पर किया है।

अब 6 महीने में होगा TB का इलाज, नई प्रणाली को मोदी सरकार की मंजूरी

TB Treatment केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत बहु-औषधि प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टीबी) के लिए एक नई उपचार (बीपीएएलएम) पद्धति को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यह पद्धति अत्यधिक प्रभावी है और इससे एमडीआर-टीबी का उपचार कम समय में संभव है। इस उपचार में प्रीटोमानिड नामक एक नई टीबी रोधी दवा को शामिल किया गया है।

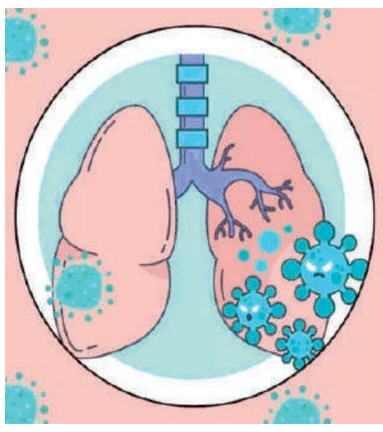

नई दिल्ली। अब केवल छह महीने में टीबी का प्रभावी उपचार संभव होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मल्टी- ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एमडीआर-टीबी) या दवा प्रतिरोधिक तपेदिक के उपचार की नई पद्धति को मंजूरी दे दी है।

इस उपचार में प्रीटोमानिड नामक एक नई टीबी रोधी दवा को बेडाक्विलाइन और लाइनज़ोलिड (मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ या बिना) के साथ शामिल किया गया है।

एमडीआर-टीबी का पारंपरिक उपचार

भारत में एमडीआर-टीबी के 75,000 रोगी इस उपचार विधि का लाभ उठा सकेंगे। इस समय एमडीआर-टीबी का पारंपरिक उपचार 20 महीने तक चलता है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

टीबी उपचार के लिए दवाई

मंत्रालय ने राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत टीबी के उपचार के लिए बेहद प्रभावी उपचार 'बीपीएएलएम' को स्वीकृति दे दी है। 'बीपीएएलएम' पद्धति में चार दवाएं- प्रीटोमैनिड, बेडेक्विलिन और लिनजोलिड और माक्सीफ्लाक्सेसिन - शामिल हैं।

लाइसेंस को मंजूरी

यह पुरानी एमडीआर-टीबी उपचार विधि की तुलना में सुरक्षित, अधिक प्रभावी है। 'प्रीटोमैनिड' को भारत में उपयोग के लिए स्वीकृति व लाइसेंस केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) पहले ही दे चुका है।

नए उपचार को मंजूरी

बीपीएएलएम पद्धति काफी कारगर है। यह एमडीआर-टीबी को केवल छह महीने में ठीक कर सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के परामर्श के बाद टीबी के इस नए उपचार को मंजूरी दी।

2025 तक टीबी मुक्त भारत

मंजूरी देने से पहले इस उपचार की देशभर के विशेषज्ञों ने गहन समीक्षा की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत भारत ने 2025 तक टीबी से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा है।

सीरवी समाज शमशाबाद (बड़ेर) में बीज महोत्सव व 10वा वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद। सीरवी समाज शमशाबाद बड़ेर प्रांगण में माँ आईजी का 609वां अवतरण दिवस एवं समाज का 10वां वार्षिक सम्मेलन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज यहां सचिव भोलाराम पंवार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार,भादवा सुदी एकम पर बुधवार को श्री आई माता जी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से अलौकिक रूप से सजाया गया। शाम समय सभी भक्तों ने श्री आई माता जी की भावपूर्ण सामूहिक आरती की। हरिद्वार गायत्री परिवार से पधारे मांगीलाल जी कोटवाल द्वारा 108 दीपोत्सव प्रज्जलित किया गया। तत्पश्चात सभी भक्तों ने आंनद पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। लगभग 9:30 बजे से भजन गायक माणकचन्द प्रजापत चावण्डिया पाली एण्ड पार्टी ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। बहुत ही सुन्दर एवं शानदार भजनों का कार्यक्रम रहा।बोलीयो कार्यक्रम ऑनलाइन द्वारा बोलियां चल रही थी उसे पूर्ण किया। निम्न बोलीदाताओं ने बोलियां का लाभ लिया। इसमें बोली दाता- १ माताजी के पट खोलने की - सुनील पुत्र श्री राजु राम जी परिहार (शमसाबाद) २- माताजी के तिलक की - चेलाराम काग(राजेन्द्र नगर) - माताजी के हार की - लुम्बाराम मूलेवा (महेश्वरम) ४-माताजी की चुनड़ी की- राजु राम 9666 (तलकोन्डापल्ली) ५- माता जी के नारीयल अगरबत्ती की-तेजाराम चोयल (महेश्वरम) ६- पांचो भगवान पौसाक की -धरमाराम काग (तुकुगुडा) ७-खेतलाजी पट हार अगरबत्ती की- रमेश काग (शमसाबाद)८- गणेश जी पट हार अगरबत्ती की- धर्माराम काग (तलकोन्डापल्ली)९- हनुमान जी पट हार अगरबत्ती की- भोलाराम पंवार (कन्दुकूर)१०- रामदेव पट हार अगरबत्ती की- दीपाराम परिहार (वेलजाल)११- महाप्रसादी अर्थात माताजी को भोग की -हरजी राम काग (शमसाबाद)

चढ़ बढ़कर कर भाग लिया। गुरुवार सितम्बर को प्रातः 8:15 से श्री आई माता जी की झांकी निकाली गई।

बहुत शानदार तरीके से नाचते - झुमते गाते झांकी का प्रदर्शन रहा। उसके बाद में बोली दाताओं ने अपनी बोली से संबंधित समस्त प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं की श्रद्धा एवं भावपूर्ण पूजा अर्चना संपन्न की। गणेश वंदना एवं श्री आई माता जी की आरती समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों ने भावपूर्ण संपन्न की। तत्पश्चात सभी भक्तों ने नाश्ते (इटली डोसा जलेबी)का आनन्द उठाया।

सचिव भोलाराम पंवार ने मंच कार्यक्रम शुरू किया।एवं महिला मंडल की सचिव भारती परिहारिया ने भी बहुत शानदार तरीके से मंच का संचालन शुरू किया।लगभग 11:30 बजे से महिला मंडल समिति की सचिव भारती परिहारिया, सांस्कृतिक मंत्री सुशीला देवी काग एवं गणकी देवी राठौड़ के नेतृत्व में नन्हे मुन्ने बाल-कलाकरों ने राजस्थान की संस्कृति की झलक अपने सामाजिक परिवेश में शालीनता के साथ भक्ति भावपूर्ण तरीके से नृत्य करके प्रस्तुत किये। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि (तेलंगाना प्रांत के अध्यक्ष) एवं संरक्षक हरजी राम काग और अध्यक्ष श्री आसाराम जी गहलोत , सचिव भोलाराम पंवार,शिक्षा समिति के अध्यक्ष केसाराम काग, सचिव -भीकाराम काग, महिला मंडल के अध्यक्षा पारी देवी काग, सचिव भारती परिहारिया और रायपुर पंचायत समिति के सदस्य गौरी देवी काग मंच पर विराजमान हुए। साथ ही गायत्री परिवार के मांगीलाल जी कोटवाल, राष्ट्रीय कवि विष्णु कुमार शर्मा भी मंच पर विराजमान हुए।

विशेष अतिथि रुप में पधारे-श्री सुगनाराम जी (कमांडेंट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद) साथ ही श्री बुधराज जी का (पुलिस विभाग जोधपुर) भी मंचासीन हुए। समाज के पदाधिकारी द्वारा इन सभी अतिथियों का साफा एवं हार द्वारा स्वागत किया गया। विशेष अतिथि सुगनाराम जी (कमोडेंट) ने सीरवी समाज की संस्कृति की भूरी -भूरी प्रशंसा करते हुए श्री आई माता जी की अखंड ज्योति को नमन करते हुए शुभकामनाएं दी।

कार्यकारिणी समिति ,शिक्षा समिति एवं महिला मंडल के पदाधिकारी ने और सदस्यों द्वारा सभी बोली दाताओं का साफा एवं हार द्वारा बहुमन किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बालक बालिकाओं ,कलाकारों एवं नृत्यांगनाओं सभी को पुरस्कार देकर दानदाताओं द्वारा दी हुई राशि भेंट की।कोषाध्यक्ष राजु राम परिहार वर्ष भर के आय -व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। वहाँ उपस्थित सभी आई भक्तों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम का खुब आनंद लिया। और माता जी का प्रसाद ग्रहण किया।

आज इस पुरे कार्यक्रम में कार्यकारिणी समिति, शिक्षा समिति एवं महिला मंडल के पदाधिकारियों व तीनों समितियो के समस्त सदस्यो का विशेष सहयोग रहा। समाज के अन्य गणमान्य महानुभाव की उपस्थिति में हर्ष उल्लास के साथ भादवा सुदी बीज महोत्सव सम्पन्न हुआ।

पुरानी पुस्तकों को आर्थिक रुप से कमजोर और जरूरतमंदों को दान करें : डॉ उमेश शर्मा

संजय साग़र सिंह

पढ़ना सब का अधिकार है, दुनिया को पढ़ों और तेज बनो-किताबें पढ़ों तथा पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं तथा स्वयं भी शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित बनाएं क्योंकि पुस्तके साहित्य समाज का दर्पण होती हैं। पुस्तकों से हमे ज्ञान और शिक्षा मिलती है।

आइए हम सब मिलकर पुस्तक के प्रति प्रेम तथा अध्ययन के प्रति लोगों को जागरूक करें। जिससे लोग पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं, स्वयं भी शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित बनाएं लेकिन किताबो के बिना पढाई करना आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता हैं। इसलिए हमारा सभी से विनम्र आग्रह हैं कि सक्षम लोग पुरानी पुस्तकों को आर्थिक रुप से बंचित, कमजोर और जरूरतमंदों को दान करें। तभी प्रधानमंत्री जी का इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना पूरा हो सकेगा। आइए देश व समाज की उन्नयन एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सभी एक साथ मिलकर योगदान दें और हम सब मिलकर पुस्तक के प्रति प्रेम तथा अध्ययन के प्रति लोगों को जागरूक करें। जिससे लोग पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं, स्वयं भी शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित बनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षा के मत्व हो सभी को समझाते हुए उत्तर प्रदेश के सुप्रशिद्ध समाज सेवक डॉ उमेश शर्मा ये बाते कहीं।

उत्तर प्रदेश के सुप्रशिद्ध समाज सेवक डॉ उमेश शर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आगे कहा, जीवन में अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हमे अच्छे पुस्तकों को पढना बहुत ही जरुरी होता हैं। क्योंकि किताबें वो अनमोल चीज हैं जिससे हमे सच्चा ज्ञान मिलता हैं। किताबें हमारे जीवन का आधार हैं। जीवन में सीख हमे किताबों से ही मिलती हैं। पुस्तक वो चीज़ हैं जो हम पहले स्कूल में पढ़ते है, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते हैं। पुस्तक एक ऐसी वस्तु हैं, जिसमे ज्ञान का काफी मात्रा में बोद्ध होता हैं। जीवन में ज्ञान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुस्तकों का होना जरुरी हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तेयारी करते हैं तो तो आप को कई अलग अलग प्रकार की पुस्तके पढने चाहिए, जैसे भूगोल, इतिहास और राजनीती की किताबें आदि। किताबो को पढ़ने से भी की काफी ज्ञान की प्राप्ति होती हैं। अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और एक सुप्त अंतः करणः यही आदर्श जीवन है। किताबों की यही तो ख़ास बात है, वे आपको आपके पैर हिलाए बिना यात्रा करा देते हैं। वहीं,जिन किताबों को दुनिया अनैतिक कहती है, वही ऐसी किताबें हैं, जो दुनिया को अपनी शरण में ले आती है। यदि कोई ऐसी किताब है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं लिखी गई है, तो आपको उसे अवश्य ही लिखना चाहिए। किताबों से हमे हमारे जीवन से जुडी ज्ञान की बाते जानने और सीखने को मिलती हैं। जैसा की हम जानते हैं कि तकनीक आज से समय की मांग हैं, उसके लिए हमे तकनिकी किताबो का पढना भी जरुरी होता हैं। आप सकारात्मक किताबें पढ़े क्योंकि किताब जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं होता। हमारे जीवन में पुस्तकों का काफी महत्त्व हैं। पुस्तकों में काफी ज्ञान उपलब्ध होता हैं और उस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं।

उन्होंने कहा, पुस्तकों में वो ताक़त होती हैं जो हमारे अंधकाररुपी जीवन में उजाला भर सकती हैं। पुस्तकों से हमे काफी कुछ सीखने को मिलता हैं। पुस्तकों का जीवन में होना अपने आप में एक अच्छी बात होती हैं। अगर आपके पास एक अच्छी पुस्तक हैं तो आप उसके ज्ञान से दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। पुस्तक को पढने से हमे काफी अच्छा लगता हैं। पुस्तक हमारे साथ एक सच्चे दोस्त की तरह रहती हैं। पुस्तकों में ज्ञान का भंडार होता हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और उनको अधिग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान या किसी भी चीज़ के बारे में सीखने के लिए हमे सबसे पहले पुस्तकों की ही आवश्यकता होती हैं। पुस्तके हर आयु के लिए उपयोगी होती हैं, फिर चाहे वो छोटे हो या बड़े या बुजुर्ग, हर आयु के व्यक्तियों के लिए पुस्तक काफी महत्वपूर्ण होती हैं। किताबो का महत्त्व वो व्यक्ति ही जानता हैं, जिसने किताबो के लिए संघर्ष किया हो। ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए पुस्तकों का काफी अहम रोल होता हैं। पुस्तकों के भंडार में हमे कई ऐसे स्त्रोत मिल जाते हैं जिनके जरिये हम अपने ज्ञान को बडा सकते हैं।

श्री शर्मा ने आगे बताया कि पुस्तकों का इतिहास आज से नही बल्कि काफी प्राचीन समय से हैं। पुस्तकों को प्राचीन काल से हमारे महापुरुष लिखते आ रहे हैं। पुस्तकों से हमे काफी कुछ सीखने को मिलता हैं। कई ऐसी पुस्तके हैं जो हमे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान देती हैं। हमारे देश के कई महापुरुष ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने पुस्तके लिखी हैं और उन पुस्तकों के ज्ञान अपने जीवन में उतारते हैं। पुस्तकों से मनुष्य को ज्ञान और शिक्षा मिलती है।इसलिए आप सकारात्मक किताबें पढ़े क्योंकि किताब जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं होता। पुस्तकें ज्ञान का महत्वपूर्ण श्रोत्र है। अपनी पूर्ण क्षमता से अध्ययन कर अपने ज्ञान रूपी क्षितिज का विस्तार करें तथा देश व समाज की उन्नयन एवं नए भारत के निर्माण में योगदान दें।

नुआपडा नेबोदय स्कूल के अधिकारियों ने 7 छात्रों और दो छात्राओं को निलंबित कर दिया हैं

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर् : नुआपडा तारबोड नेबोदय स्कूल में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे कक्षा 2 के 7 छात्र अरबाली में 10वीं कक्षा के सीनियर के घर में घुस गए। फिर उन्होंने एक-एक करके 22 छात्रों को बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें लाठी, लोहे की रॉड और रस्सियों से पीटा। सीनियर छात्रों की पिटाई से 10वीं के 22 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गये। सभी गंभीर छात्रों को जिला प्रमुख अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि छात्र सिर से पैर तक गंभीर रूप से घायल था। बताया गया है कि एक छात्र के कमेंट की वजह से ऐसी दुर्लभ घटना घटी है। खबर मिलने के बाद अभिभावक नेबोदय स्कूल पहुंचे और तारबोड पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पहुंची । वहीं 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी बात रखते हुए पिटाई करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नुआपाड़ा जिला कलेक्टर मधुसूदन दास ने कहा कि उक्त छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस घटना के बाद नेबोदय स्कूल के वाडेन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेबोदय स्कूल के अधिकारियों ने 7 छात्रों और दो छात्राओं को निलंबित कर दिया है। निलंबित छात्र स्कूल नहीं जा सकते। आप हॉस्टल में भी नहीं रह सकते। नीलमवान के बाद आज सुबह से नुआपाड़ा जिले के तारबोड नेबोदाई में चल रहा 10वीं कक्षा के छात्रों का आंदोलन वापस ले लिया गया है।

त्रिशूला सुभाष चंद्र बोस ब्रिज पर भीषण दुर्घटना, 2 लोगों की गई जान

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा , **भुबनेस्वर् :**त्रिशूला सुभाष चंद्र बोस ब्रिज पर भीषण दुर्घटना। 2 लोगों की गई जान। एक टाटा मैजिक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है ।कटक के सुभाषचंद्र बोस ब्रिज के पास एक भीषण हादसा हो गया।एक स्कूटर को विपरीत दिशा से आ रही टाटा मैजिक ने टक्कर मार दी। बताया गया है कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और दुर्घटना करने वाली पिकअप वैन और स्कूटी को जब्त कर लिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023